श्रीमती सविता बहिन : कैन्डीडेट के भाई की बहू मैंने नहीं कहा । कार्यकर्ता और उसकी पत्नी को . . .

श्री चरण सिंह : कार्यकर्ता और उसकी पत्नी को ? एक ही बात है । कोई फर्क नहीं पड़ा । तो उनको नंगा कर दिया । क्या मैं जान सकता हूं कि माननीया सविता जी वहां मौजूद थीं ?

श्रीमती सविता बहिन : मेरे पास रिपोर्ट आई है जो कार्यकर्ताओं ने दी हैं ।

श्री चरण सिंह : हम यही समझते थे । वरना ऐसी बातें नहीं कर सकतीं हैं . . .

श्रीमती सविता बहिन : इन दोनों पति-पत्नी को कार्यकर्ताओं ने बाहर खींच कर निकाला, साड़ी खींच कर उतार दी ।

श्री चरण सिंह : मैं तो यह जानना चाह रहा था कि आपके इल्म की बात है या आपकी इन्फारमेशन की बात है ? इल्म की बात हो ही नहीं सकती थी । यह आपको गलत इत्तिला मिली है । अगर ऐसा होता तो अखबारों में निकलता । जिनके साथ अन्याय हुआ वे चिट्ठी लिखते, पुलिस में रिपोर्ट करते । आई०जी० दूर नहीं सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस दूर नहीं है । लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया है, आप कार्यकर्ता का नाम मेरे पास लिख कर भेज दें तो मैं आज ही आई०जी० को लिख कर उनसे कह दूं कि इसकी डीटेल्स भेज दें ।

THE BUDGET (GENERAL) 1977-78 GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

श्री भानु प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं वर्ष 1977-78 वर्ष के बजट के बारे में अपने विचार सदन के समक्ष रखने के लिये खड़ा हुआ हूं । अपना देश बहुत विशाल है। इसकी समस्याएं भी बहुत जटिल हैं। इसलिए बजट के पहलू भी अनेक हैं । बजट के सारे पहलूओं पर प्रकाश डालना न तो समय की कमी के कारण सम्भव है और न ही मैं अपने आप को सभी विषयों का विशेषज्ञ ही समझता हूं । अतः थोड़ा सा समय जो मुझे मिलेगा उस का मैं यह दिखाने के लिये प्रयोग करना चाहता हूं कि बजट का कृषकों से और कृषि से क्या संबंध है । इसी दायरे में बांध कर मैं अपनी बातें कहूंगा ।

लेकिन पहले जो मुझसे पूर्ववक्ता उधर से बोले थे उनकी कुछ बातों का उत्तर देना चाहता हूं । पहली बात उन्होंने यह कही थी कि सिचाई के लिये यद्यपि बजट भाषण कहा गया है कि उसका विस्तार दूनी गति से होना चाहिये लेकिन उसके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मैं उन के और पूरे सदन की जानकारी के लिय कुछ आंकड़े पिछले वर्ष और इस वर्ष की तुलना करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं । पिछले वर्ष बड़ी सिचाई योजनाओं और मध्यम सिचाई योजनाओं के लिये 692 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी थी । इस वर्ष 1039 करोड़ रुपये रखे गये हैं । छोटी योजनाओं पर पिछले वर्ष 154 करोड़ रुपये रखे गये थे । इस वर्ष 205 करोड़ रुपये रखे गये हैं । बड़ी और छोटी योजनाओं का योग किया जाये तो पिछले वर्ष कुल धन 846 करोड़ था । इस वर्ष यह 1244 करोड़ रुपये हो जाता है । प्रतिशत के रूप में यह लगभग 50 फीसदी अधिक है उस धनराशि से जो पिछले वर्ष सिचाई की योजनाओं के लिये रखी गई थी । श्रीमन्, मेरा ऐसा विचार है कि यदि जनता सरकार सिचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने में जो धांधली और भ्रष्टाचार व्याप्त था उसे रोक सकेगी तो यह 50 फीसदी अधिक धन ही पर्याप्त होगा इस देश में सिचाई की व्यवस्था को दुगुनी गति से बढ़ाने के लिये ।

श्रीमन्, दूसरी बात यह कही गयी कि जनता पार्टी जब से जनता सरकार बनी है मंहगाई को रोकने में असफल रही है । यह आरोप लगाया गया है कि प्रति मास एक प्रतिशत मंहगाई बढ़ रही है । श्रीमन्, संयोग से मेरे पास आंकिक समीक्षा है और आपकी इजाजत से मैं अप्रैल 76 से लेकर मार्च 77 का सभी वस्तुओं का होल-सेल प्राइस-एन्डैक्स पढ़ना चाहता हूं : अप्रैल में 166.2, मई में 169.3, जून में 171.5, जुलाई में 177.6, अगस्त में 178.5, सितम्बर में 179.5, अक्तूबर में 177.6, नवम्बर में में 176.8, दिसम्बर में 177.3, जनवरी में 178.5, फरवरी में 181.7, मार्च में 1821 श्रीमन्, यदि साल भर की वृद्धि जोड़ी जाये तो जो आरोप उन्होंने लगाया है एक प्रतिशत प्रति-मास मूल्यों में वृद्धि का उस से पहले भी कम नहीं हुआ । यह स्थिति तब थी जब उन की

[श्री भानु प्रताप सिंह]

हुकूमत को सारे अधिकार मीसा, डी०आई० आर० और इमरजेंसी के प्राप्त थे । उस वक्त की यह स्थिति थी । अब बावजूद इसके कि हम उन अधिकारों का प्रयोग नहीं करते फिर भी मंहगाई उस गति से अधिक नहीं बढ़ी है जितनी उनके शासन काल में बढ़ी थी ।

श्रीमन्, अब मैं अपनी बातों की ओर आता हूं जो बड़ी मौलिक बातें हैं । कुछ क्षेत्रों में जनता पार्टी ने जो यह घोषित किया कि वह कृषि विकास और ग्रामीण विकास की ओर अधिक ध्यान देगी इसकी आलोचनायें हुई हैं । कुछ लोगों ने इस नीति को ही गलत बताया है । श्रीमन्, मैं कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूं विशेषकर इस लिये भी कि मुझ से पूर्ववक्ता ने इस बजट को दकिया-नूसी बजट बताया है । कहा है कि यह स्टैटिक बजट है । यह एकाउन्टेंट्स बजट है, यह स्टैड स्टिल बजट है । श्रीमन्, मैं तो स्टैड स्टिल को पीछे जाने वालों से बेहतर समझता हूं । मैं जो तथ्य रखने जा रहा हूं उनसे स्पष्ट होता है कि जिन सोशल इंजीनियरिंग की बड़ी प्रशंसा की गई, और जैसे डायनमिक और माडर्न बजट पेश किये जाते रहे हैं उनका क्या परिणाम निकला है और उनसे क्या पाया इस देश के 80 प्रतिशत लोगों ने । सब से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि 1950-51 से जब से नियोजन इस देश में प्रारम्भ हुआ इस बात की कोशिश होती रही है कि देश खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर बने । परन्तु परिणाम क्या है ? मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं । 1951, 52 और 53 के तीन वर्षों में इस देश में जब नियोजन प्रारम्भ हुआ था 10.77 मिलियन टन अनाज विदेशों से मंगाया गया । अब जो अन्तिम तीन वर्ष इस डायनमिक और सोशल इंजीनियरिंग के रहे हैं अर्थात् 1974, 75 और 76 में विदेशों से 18.8 मिलियन टन अनाज मंगाया गया है । अर्थात् हमारी विदेशी अन्न पर निर्भरता लगभग दूनी बढ़ गयी है । यह हुआ है आप की तथा कथित डायनमिक स्ट्रेटेजी के कारण । मैं पिछले 25,26 सालों का आप के सामने लेखा-जोखा प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस देश की कृषि व्यवस्था को आपने किस प्रकार पीछे रखा है । श्रीमन्, किसी भी स्ट्रेटेजी का भारत जैसे दरिद्र देश में जहां कि लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, सब से बड़ा मापदंड यह है कि जो भोजन प्रति व्यक्ति इस देश में मिलता है उस में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है या नहीं ।

The Vice-Chairman (Shri Ranbir Singh) in the Chair]

मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं 1961, 62 और 63 में औसत प्रति व्यक्ति जो अन्न इस देश के लोगों को मिला वह 457.8 ग्राम प्रति दिन था और अन्तिम तीन वर्षों में 1974, 75 और 76 में जैसा मैं पहले बतला चुका हूं बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों से अन्न मंगाया गया उस के बावजूद भी वह मात्रा घट कर 439.9 ग्राम ही रह गयी है । अब इस के साथ-साथ अगर हम तिलहन पर ध्यान दें, शक्कर पर ध्यान दें तो स्थिति और भी खराब हुई है । 1970-71 की तुलना में किस प्रकार दालों की खपत में, तेल की खपत में, शक्कर की खपत में और कपड़े की खपत में गिरावट आयी है उसे भी मैं बता देना चाहता हूं । 1970-71 में 4.5 किलोग्राम तिलहन जिस में वनस्पति भी शामिल है प्रति व्यक्ति औसतन इस देश में प्राप्त हुआ और अभी-अभी जो वर्ष बीता है उस में 4.3 किलोग्राम ही प्राप्त हुआ । शक्कर 7.3 किलोग्राम पहले मिलती थी । अभी जो वर्ष बीता है 6.1 किलोग्राम रह गयी । कपड़ा 1955-56 में जहां 14.4 मीटर मिलता था अब 12.6 मीटर रह गया है । भोजन की कुल मात्रा में कमी हुई है, दालें जो गरीबों के लिये प्रोटीन का एक मात्र स्रोत है, उनकी स्थिति यह है कि सन 1956-57 और 1961-62 में करीब 70 ग्राम दालें प्रतिदिन मिलती थीं, अब वह घट करके 40, 42, और 43 ग्राम हो गई है । इस देश में लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और यदि मैं कहूं कि जितनी आवश्यकता है उसका दो तिहाई से अधिक नहीं मिलता तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । यदि कैलोरीज की शक्ल में देखें तो भारतवासियों को सबसे कम भोजन मिलता है । अब चार-चार योजनायें समाप्त होने के बाद उसका नतीजा यह है कि तिलहन, दलहन, कपड़े आदि की खपत में गिरावट आई है तो मैं प्लानिंग की ऐसी स्ट्रेटजी को, ह्यूमन इंजीनियरिंग को तिलांजलि दे देना बेहतर समझता हूं ।

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । प्रायः यह कहा जाता है कि 1950-51 में जितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ

था उसके दुगुने से अधिक अब होता है । श्रीमन्, मैं इस सदन को आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि इस धोखे में नहीं रहना चाहिए । जब से नियोजन आरम्भ हुआ, 1951 और 1961 के बीच में कृषि की प्रगति ज्यादा तेज रही है । अगर हिसाब लगाया जाए तो 2.6 प्रतिशत कृषि का उत्पादन प्रतिवर्ष पहले दस वर्षों में बढ़ता रहा और इधर 1960-61 के बाद के 16 वर्षों में यह उत्पादन वृद्धि गिरकर 1.9 प्रतिशत रह गई है । श्रीमन्, आबादी की वृद्धि 1.9 प्रतिशत से अधिक है । हमारी कृषि का उत्पादन आबादी की वृद्धि की तुलना में कम है और पिछले दस वर्षों में और भी कम हुआ, यह स्थिति है ।

श्रीमन्, अब मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि आखिर इन सब नीतियों का गांवों में रहने वालों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है । यह सरकार यह सरकार नहीं पहले वाली सरकार, इसके आंकड़े कभी नहीं प्रकाशित करती थी कि ग्रामीणों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और शहर में रहने वालों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है । ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु जो कृषि में पैदावार होती है उसके मूल्य को कृषि कार्य में लगी हुई आबादी में बांट दें और कृषि से भिन्न उत्पादन का जितना मूल्य है उसे शहरों में रहने वाली आबादी की संख्या से विभाजित कर दें तो यह नतीजा निकलेगा कि 1950-51 में ग्रामीण निवासियों की औसत उपज 197.80 रुपये की थी यह 1976-77 में घटकर 196.50 रुपये रह गई । इसकी तुलना में शहर में रहने वालों की आमदनी या उपज का मूल्य जो पहले 399.40 रुपये था, वह 821.90 रुपए हो गया। श्रीमन्, भूतपूर्व सरकार सामाजिक न्याय की बड़ी बातें किया करती थी । गरीबों और अमीरों का अन्तर मिटाने की बात करती थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनको यह दिखाई नहीं दिया कि शहरों और गांवों में रहने वालों के बीच खाई कितनी बढ़ती जा रही थी? 1950-51 में गांवों और शहरों में रहने वालों की आमदनी का अनुपात लगभग 1 और 2 का था, यह बढ़कर आपके डाइनैमिक इंजीनियरिंग वगैरह जो कुछ भी आप कहते हैं, उसके फलस्वरूप 1 और 4 का हो गया है। श्रीमन्, मैं इस पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं कि ऐसा सब क्यों हुआ । तीन प्रश्न उठते हैं—पहला यह कि क्या हमारे देश की भूमि और जलवायु ऐसी है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाया ही नहीं जा सकता, दूसरा यह कि क्या हमारे देश के किसान ऐसे मूर्ख और अनपढ़ हैं कि वे नई विधि की खेती को अपना ही नहीं सकते और तीसरा यह कि क्या यह सब सरकारी नीतियों के फलस्वरूप तो नहीं हुआ है । श्रीमन्, जहां तक देश की भूमि और जलवायु की क्षमता का प्रश्न है, एक कृषक होने के नाते मैं बिना संकोच यह दावा करता हूं, क्योंकि मुझे विदेशों में जाकर वहां की कृषि को देखने का भी अवसर मिला है, कि भारत भूमि की जो क्षमता है कृषि उत्पादन की वह अद्वितीय है । शायद ही संसार में कोई देश ऐसा हो जहां इतनी पैदावार प्रति हेक्टर संभव हो। यह मैं केवल जबानी बातें नहीं करता हूं । जो नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर बना था उसकी रिपोर्ट नेशनल डिमोंस्ट्रेशन्स के नतीजे प्रकाशित हैं । इन प्रदर्शनों पर खेती के सभी साधन इकट्ठे करके यह देखा जाता रहा है कि खेती की पैदावार कितनी की जा सकती । उसको देखने से पता चलता है कि 7 से 13 टन प्रति हैक्टर की उत्पादन क्षमता हमारी भूमि की है । कई वर्षों का इसमें हिसाब-किताब है । औसत 10 टन प्रति हैक्टर पैदावार माना जा सकता है । यह एक-दो स्थानों के आंकड़े नहीं हैं एक दो राज्यों के नहीं हैं सारे देश के सभी राज्यों में हजारों जगह डिमोंस्ट्रेशन करके यह सिद्ध कर दिखाया गया कि यदि कृषि के सारे साधन उपलब्ध कराये जायें तो इस देश की उत्पादन क्षमता 10 टन प्रति हैक्टर हो सकती है ।

दूसरा प्रश्न यह है कि यदि भूमि में क्षमता है तो क्या इस देश के किसान हो इतने गये गुजरे हैं कि पैदावार बढ़ा नहीं सकते । श्रीमन् इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी उन्हें अवसर मिला है तो इस देश के किसानों ने वह कर दिखाया है जो शायद दुनिया के दूसरे किसानों ने न किया हो । केवल छः वर्षों के अंदर गेहूं का उत्पादन इस देश के किसानों ने ढाई गुना अधिक बढ़ा कर दिखाया है परन्तु उसके बाद उनका शोषण शुरू हुआ । मूल्यों में उनके साथ अन्याय हुआ, गल्ले का व्यापार अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई और किसानों को ऐसा समझा गया जैसे वे किसी किस्म के जानवर हैं । उन्हें अधिक उत्पादन का लाभ नहीं दिया गया ।

[श्री भानु प्रताह सिंह]

घोषणा की सारी योजनाएं बनीं । उसके बाद प्रगति रुक गई । कुछ लोग सोच सकते हैं कि हमारे पास 17-18 मिलियन टन अनाज का भंडार है इसलिये चिंता करने की आवश्यकता नहीं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें से लगभग आधा विदेशों से मंगाया हुआ अन्न है । जो पैदावार सन् 1976-77 में हुई है 111 मिलियन टन की वह देश के लोगों का पेट भरने के लिये पर्याप्त नहीं है । जो कमी है उसको पूरा करने के लिये हमें विदेशों से अन्न मंगाना पड़ेगा या जैसा कि हमेशा होता रहा है बहुत से लोग इस देश में आधा पेट भूखे रहेंगे । मेरा स्पष्ट मत है कि जो नीतियां अपनाई गई थीं और जिनको बदलने में अभी भी कुछ लोगों को संकोच है । यदि उन्हें बदला नहीं गया तो इस देश में वह दिन दूर नहीं जब बहुत से लोग भूखों मरेंगे, अकाल की स्थिति फिर पैदा होगी । यह कहना कि 10 वर्षों में गरीबी दूर हो जाएगी मैं समझता हूं तब तक संभव नहीं होगा जब तक पूरा ध्यान खेती की उन्नति की ओर नहीं दिया जायेगा । बहुत से लोग कहते हैं कि यदि खेती पर ही सारा ध्यान दिया गया तो उद्योगों की अवहेलना होगी ? मैं यह नहीं चाहता कि उद्योगों की अवहेलना की जाये । बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो खेती के लिए भी लाभदायक हैं । हम तो सिर्फ यह कहते हैं कि केवल कुछ वर्षों तक किसानों और देश की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक ध्यान और धन कृषि के विकास की ओर लगाइये ।

श्रीमन्, ऐसा मानता हूं कि एकायक कोई परिवर्तन संभव नहीं है । हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बात को अपने भाषण में समझाने की कोशिश की है कि खेती पर अपने रिसोर्सेज को डायवर्ट करने में अनेक कठिनाइयां हैं । उन्होंने यह बतलाया है कि जो योजनाएं चल रही हैं या जो आधी पूरी हुई हैं उनको कैसे बन्द किया जा सकता है ? अगर उनको बन्द कर दिया जाएगा तो जो उन पर अब तक व्यय किया गया है वह सब नष्ट हो जाएगा । इसलिए उनको चलाये रखना ही पड़ेगा । ऐसी स्थिति में धन का और अधिक डायवर्जन खेती की तरफ नहीं हो सकता है । उन्होंने समय का भी अभाव बताया है । यह बात भी सही है कि सन् 1978-79 के लिए जो बजट प्रस्ताव आएंगे उन पर आज से ही विचार करना होगा । ऐसे विषयों पर सात आठ महीने पहले से विचार हो तब ठीक योजना बनती है । इसके अलावा जितनी भी योजनाएं बन सकती हैं उनके संबंध में राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श करना होता है क्योंकि अन्त में राज्य सरकारों को उनका कार्यान्वियन करना होता है । श्रीमन् यह सब होते हुए भी और यह मानते हुए भी कि सरकार के सामने कठिनाइयां हैं यह कहना पड़ता है कि ग्रामीण लोगों को जनता सरकार से जो आशा थी जो अपेक्षा थी वह पूरी हुई दिखाई नहीं देती है । मैं विशेषकर मूल्यों के संबंध में कहना चाहता हूं । जनता पार्टी के मैनिफैस्टो में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि कृषि वस्तुओं के मूल्य अन्य वस्तुओं के मूल्यों की बराबरी में दिये जायेंगे अर्थात् कृषि वस्तुओं के मूल्य समता के सिद्धान्त के अनुसार निश्चित होंगे । जिस वक्त गेहूं की कीमतें निश्चित की जा रही थीं उस वक्त मात्र 5 रु० की वृद्धि करके यह कहा गया था कि कृषि साधन तथा दूसरी वस्तुएं भी कम कीमत पर मुहैया की जाएंगी । मैं मानता हूं कि अगर अनाज की कीमतें ज्यादा होंगी तो इस देश में गरीबों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । इसलिए अच्छा तरीका यही था कि कृषि और कृषकों के उपयोग में आने वाली चीजों की कीमतें गिराई जायें । मैं अन्य वस्तुओं की चर्चा तो नहीं करना चाहता, लेकिन केवल खेती में काम आने वाली चीजों के विषय में कहना चाहता हूं कि किस तरह से उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है और किस तरह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है । सन् 1970-71 के वर्ष में मूल्यों को यदि सौ मान लिया जाए तो फर्टिलाइजर की कीमतें 178.6 हो गई हैं और इंसेक्टिसाईड्स की कीमतें 232.7 हो गई । बिजली के मूल्य का सूचकांक 175.8 हो गया है, डीजल का 213 और लुब्रीकेटिंग आयल का 314 जबकि गेहूं का मूल्य केवल 40 फीसदी बढ़ा है । चावल की प्राक्योरमेन्ट प्राइस बढ़ी है । मैं इस समय और बातें नहीं कहना चाहता हूं । परन्तु यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर की कीमत गिरना नितान्त आवश्यक है । यह न केवल किसानों को राहत पहुंचाने के लिये अपितु यदि जनता पार्टी को किसानों से अपना वायदे पूरे करने हैं तो उस

दिशा में जो पहला कदम हो सकता है, वह यही है । इसकी अहमियत यह भी है कि यह सबसे कम समय में सबसे अधिक लोगों की गरीबी दूर करने का माध्यम भी बन सकता है । आज फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़े, तो तीन महीने के अन्दर उसके नतीजे सामने आ सकते हैं । बड़े उद्योगों में या छोटे उद्योगों में जितना धन लगाया जाता है, उसके नतीजे दो-दो, चार-चार और दस-दस साल तक नहीं मिलते । बड़ी-बड़ी योजनाएं जो बन रही हैं, उनका परिणाम आने में काफी समय लगेगा । यही एक ऐसा कदम है कि तत्काल तीन महीने के अन्दर उसका परिणाम मिल सकता है । यदि सरकार के सामने ऐसी कठिनाइयां होतीं कि उत्पादन व्यय ही बहुत ज्यादा होता तो यह मजबूरी होती । लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि उर्वरक के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बहुत है । यह कहा जा सकता है कि अगर फर्टिलाइजर की कीमत गिराई जायेगी तो 115 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो । उनके आंकड़ों पर मैं सन्देह नहीं करता हूं, लेकिन इसके जो नतीजे निकलेंगे वह देश के लिये बहुत हितकर सिद्ध होंगे । हम अन्न मंगाकर 460 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं । लेकिन देश के प्रोक्योरमेन्ट और विदेश से मंगाये गये अनाज का अलग-अलग हिसाब लगायें तो मालूम होगा कि केवल विदेशों से मंगाये गये अनाज पर 300 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी गई है । हम दूसरे देशों के किसानों को सब्सिडाइज्ड कर सकते हैं, उनको एक प्रकार से इनडाइरेक्ट मदद पहुंचा सकते हैं लेकिन अपने देश के किसानों के लिये 115 करोड़ रुपये छोड़ने में संकोच हो रहा है । पूरे बजट की धनराशि 15 हजार करोड़ रुपये है, क्या उसमें से 115 करोड़ नहीं छोड़ सकते ? इतनी रकम छोड़ना कोई खास मायने नहीं रखता ।

प्रश्न पूछा जाता है कि कसे डेफिसेट भी न हो और छूट भी दी जाए ? इस बारे में मैं दो उपाय बतलाना चाहता हूं । विदेशों में फर्टिलाइजर सस्ती है और आज आपके पास विदेशी मुद्रा की कमी नहीं है । आप विदेशों से फर्टिलाइजर मंगाइये और उसको आप देश में पैदा फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर बेचें । इसमें कठिनाई यह बतलाई जायेगी कि जो विदेशों से आता है, उस पर कस्टम ड्यूटी है । अगर कृषि के इनपुट्स और साधनों पर सरकार टैक्स लगाये तो कृषि की उन्नति नहीं हो सकेगी । मैं ट्रैक्टरों का उदाहरण देना चाहता हूं । आज 30—35 हार्स पावर के टैक्टर की कीमत में साढ़े 17 हजार रुपया केवल टैक्स है । अधिकांश किसान कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदते हैं । 12-13 प्रतिशत उस पर उनको सूद अदा करना पड़ता है केवल टैक्स की रकम पर ही उन्हें 2 हजार रुपये वार्षिक सूद अदा करना पड़ता है ।

मैंने कहा था कि मैं दो उपाय बतलाऊंगा । एक तो मैंने यह बताया कि विदेशों से मंगाकर उर्वरक आप किसानों को दें । विदेशों में उर्वरक इस समय सस्ते हैं । दूसरा उपाय भी मैं बतलाना चाहता हूं और वह यह है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि 410 करोड़ रुपये जो इस्पात कारखानों के विस्तार पर पिछले वर्ष लगे थे, उसकी तुलना में इस वर्ष 510 करोड़ रुपये लगाये जायेंगे । श्रीमन्, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि इस देश में जितना इस्पात का उत्पादन हो रहा है, उसकी खपत नहीं हो रही है । हम इस्पात विदेशों को भेजते हैं, सस्ते दामों पर भेजते हैं । एक विचित्र स्थिति बता दूं कि एक तरफ किसानों को कम कीमतें मिलें, इसके लिए विदेशों से अनाज मंगा कर 300 करोड़ रुपये का घाटा उठाया जाता है । दूसरी तरफ कृषि से भिन्न वस्तुएं विदेशों में हम भेज सकें इसके लिए भी 300 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है क्या यह उल्टे प्राथमिकता का परवरटिड प्रायरटीज का नमूना नहीं है । भारत जैसा कृषि प्रधान देश 300 करोड़ रुपया सब्सिडी अनाज मंगवाने के लिए दे और कृषि से भिन्न वस्तुएं, स्टील वगैरह बेचने में 300 करोड़ रुपय की फिर सब्सिडी दे ! श्रीमन्, यदि किसानों के साथ इन्साफ करना है तो जनता पार्टी की हकूमत को इस दौड़ में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर कांग्रेस सरकार के 400 करोड़ रुपये इस्पात के कारखानों के विकास के लिए रखे थे तो हम उसका सवाया रखें । इस्पात के कारखानों का विकास इन्तजार कर सकता है लेकिन स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में 'कृषि इन्तजार नहीं कर सकती' । इस्पात की कमी होने की सम्भावना आगे हो सकती है जब कि देश का विकास हो । किन्तु यह तभी सम्भव होगा जब कृषकों के पास खरीदने के लिए परचेजिंग

[श्री भानु प्रताप सिंह]

पावर होगा । जो थोड़ा इस्पात पैदा होता है, थोड़ा सा कैमिकल पैदा होता है, थोड़ा सा फर्टिलाइजर पैदा होता है, थोड़े से कपड़े पैदा होते हैं, आखिर क्यों नहीं बिकते हैं । क्या कारण है कि इन सब की खपत कम होती जा रही है । इसका कारण केवल यही है कि गांव में बसे हुए 80 प्रतिशत लोगों की क्रय क्षमता निरन्तर गिरती जा रही है और कारखाने चाहे इस्पात के हों, चाहे फर्टिलाइजर के हों यह सब के सब जो सामान बनाएंगे, हो सकता है कि गवर्नमेंट विदेशों में नुकसान उठा कर बेचती रहे, लेकिन यदि किसानों के साथ न्याय नहीं होगा तो न इस देश की कृषि का विकास होगा और न समृद्धि आयेगी ।

श्रीमन्, इस बजट में कम से कम मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उसका भी जिक्र कर देना आवश्यक है । इस देश के सभी बच्चों की तरफ से मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मिठाई, टाफी, वगैरह, जो बच्चे खाते हैं, उस पर रहम किया है और साथ ही साथ उन्होंने बूढ़ों के लिए भी पेंशन में 10 करोड़ रुपये बढ़ाने की व्यवस्था की है । एक और अच्छी बात है उसका भी जिक्र कर देना जरूरी है, वह है डेफिसिट फाइनेंसिंग का अन्त । आप पूछेंगे कि बच्चों के लिए कुछ किया गया है, बूढ़ों के लिए कुछ किया गया है, पर सामान्य नागरिक के लिए क्या है ? तो मैं यह कहूंगा कि सामान्य नागरिक के लिए केवल यह आशा है कि मूल्य नहीं बढ़ेंगे । मूल्यों को बढ़ाने में मुद्रास्फीति का बहुत बड़ा रोल है और यह बजट जो संतुलित-सा पेश किया गया है, इसके कारण मैं समझता हूँ । मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी । लेकिन जहां तक हमारी नीतियों को एक नयी दिशा देने, कृषि और ग्रामविकास को अधिक महत्व देने का है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ । मैं नहीं मानता कि बजट में कोई नई दिशा है। पिछले वर्ष और इस वर्ष के आंकड़े मेरे सामने हैं जो कृषि में या कृषि से संबंधित योजनाओं में लगने वाली धनराशि है । इस में कोई शक नहीं कि एबसोल्यूट टर्म्ज में रकमों को अगर देखें तो इस वर्ष रकम में वृद्धि हुई है । रकम वृद्धि 2312 करोड़ रुपये के मुकाबले 3024 करोड़ रुपये हो गई है । पिछले वर्ष जो खेती में लगने वाली रकम थी उससे इस वर्ष 31 फीसदी अधिक है । लेकिन अगर पूरे आउट ले को देखा जाए तो यह मिलेगा कि पिछले वर्ष की तुलना में पूरा आउट ले इस वर्ष 27 प्रतिशत अधिक है । जो 27 प्रतिशत सभी रकमें बढ़ गयीं तो यदि कृषि का भाग 31 फीसदी बढ़ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। ऐसा स्वीकार करने में मुझे कठिनाई है कि इस मामूली वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था में कोई मोड़ आयेगा ।

श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं इधर बैठने वाले लोगों को और उधर बैठने वाले लोगों को यह जो कृषि और ग्रामीण विकास का प्रश्न है, इस को पार्टी के प्रश्न या पार्टी के दृष्टिकोण से न देखें, यह राष्ट्रीय विषय है । अगर मेरे भाषण से कुछ लोग समझते हों कि मैंने जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना की है और इससे उनको कोई प्रसन्नता हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए । हमारी तरफ के बैठने वालों को भी कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। कृषि एक ऐसा विषय है जिस की बहुत कम लोगों को जानकारी है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जहां तक उर्वरकों के प्रयोग का संबंध है, कुछ जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि उर्वरक जमीन को खराब कर देते हैं । उनकी खपत को बढ़ाना देश के हित में नहीं है। श्रीमन्, यह बात बिलकुल गलत है । हमारे देश में अभी केवल 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर ही उर्वरकों का तत्वों के रूप में प्रयोग होता है । जब कि जापान में 250 और दूसरे वेस्टर्न यूरोप के देशों में 300 किलोग्राम होता है । अपने देश में जो रिकमेंडेशंस हैं डिपार्टमेन्ट आफ एग्रिकलचर की उसके अनुसार कोई धान और गेहूं दोनों की हाई यील्डिंग वैरायटी पैदा करना चाहे एक वर्ष में, तो उसे 480 किलोग्राम उर्वरक तत्व के रूप में प्रति हैक्टर देना पड़ेगा । उसकी तुलना में अभी हम सिर्फ 20 किलोग्रम प्रयोग कर पाए हैं । मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही लोग कह देते हैं कि अभी पिछली खरीफ में या पिछली रबी में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ गया है तो अब कीमत गिराने की आवश्यकता नहीं है । मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1970-71 और पहले भी उर्वरकों की खपत इस देश में हर पांच वर्ष में दुगनी हो जाती थी और पिछले 5 वर्षों में यह खपत 25 फीसदी भी नहीं बढ़ी है। ये आंकड़े मेरे पास हैं; मैं उनको पढ़ कर सदन का समय

नष्ट नहीं करना चाहता हूं, हम अभी उर्वरकों के पूरे प्रयोग से बहुत दूर हैं और एक तरह से उसमें ब्रेक लग गया है । उस ब्रेक का कारण यह है कि जो अनुपात है कृषि वस्तुओं के मूल्य में और उर्वरकों के मूल्य में, ट्रैक्टरों के मूल्य में, सामान्यतः सभी कृषि के साधनों के मूल्य में, उसको देखते हुए न उनकी खपत ही बढ़ेगी, न कृषि का उत्पादन ही बढ़ेगा । ऐसा मैं कहता हूं । यह मेरी बात तो रिकार्ड में आ गयी; चार-पांच वर्ष बाद, अगर ये नीतियां नहीं बदली गईं तो नतीजा हमारे सामने अच्छा नहीं आयेगा ।

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa) : Mr. Vice-Chairman. 1 wish the sentiments expressed by Shri Bhanu Pratap Singh, who happens to be a prominent leader of the Janata Party, were reflected in the Budget presented by Shri H. M. Patel. Unfortunately, this Budget does not give a direction towards self-sufficiency in food or clothing for which so emo-lionally Mr. Bhanu Pratap Singh pleaded. To me, Sir this Budget is thoroughly disappointing. It is orthodox and pedestrain and it is colourless and uninspiring. It has no special political quality nor has it any economic content. The first nine pages of the Budget speech of the Finance Minister are mere rhetoric reflecting the Janata Party manifesto and the pious wishes expressed by the Finance Minister. But the operative part, which occurs from page 10 onwards of the Budget speech of the Finance Minister in Part A does not in any way reflect the desires or the wishes expressed by the Finance Minister himself. I tried to find out what he has said in this Budget and I wanted to know what is the political philosophy that is reflected in this Budget. I wanted to know what their economic goal is, which is reflected here. I quite well know that the Janata Party has come to power only three months back and that they may plead that the time was short and that it was not possible for the Finance Minister to give a direction to its political philosophy, and to spell out its economic goal and all that. But, after all, a humble beginning could have been made and seme indication could have been given in the Budget as to what he intended to do. Judged by these standards, one is disappointed to find that this Budget has nothing in it and it is nothing but an intellectual exercise and an attempt to balance the revenue against the expenditure of the Government.

Sir, in the course of his speech, the Finance Minister had listed a number of economic ills. He speaks of the inadequate rate of growth ; he also speaks of (be uneven distribution and the uneven growth which has accentuated the regional disparities; he speaks of the rising trends in prices; and he also speaks of unemployment and so on. But I am disappointed to see this. I do not understand what he has tried to do by merely pointing out these ills. He has not tried to find proper solutions to these problems. I do not say that they can be solved immediately by one project or by the declaration of one fiscal policy. I know this cannot be done like that and so, that is not my submission. My submission is that at least some indication could have been given in the Budget as to how he is going to remedy this inadequate rate of economic growth and what particular fiscal policy he has adopted in this Budget. 1 would like to have an answer from him on this specific question whether, on the issue of inadequate growth rate, he has made any attempt to make it adequate or any attempt to go in that direction by moving at least by an inch. Nothing of that sort is found in the Budget. Similarly, he speaks of the uneven growth which has accentuated the regional disparities.

But to remove these regional disparities for the purpose of development and growth, he has not indicated any steps having been taken by him.

Similarly, Sir. so far as the rise in prices is concerned, no clear policy to check inflation is stated in the Budget. So far as unemployment is concerned he has stated in rhetorical terms and he consoles us by saying on page 8 of his speech in paragraph 25 :

> "The problem of unemployment in urban areas, particularly among the educated persons, is no less serious. The House will be happy to know that we are now working on the details of a specific scheme designed to....."

[Shri Narasingha Prasad Nanda] Therefore, he is now working on the details of a specific scheme which is yet to come. But what that specific scheme is, has not been indicated. At least a skeleton of that scheme should have been given or an outline of that scheme should have been communicated to this House. Then only the House would have been happy. By merely announcing that such a scheme will come in future will not make anybody happy nor will it solve the problem of unemployment.

Sir, so far as the question of inflation is concerned, 1 very humbly submit—I will not go into the jugglery of statistics entered into by some hon. Members—that one thing that is disturbing me is that while the Finance Minister claims that he has reduced the deficit to Rs. 72 crores, he does not clearly indicate how he is going to spend Rs. 800 crores out of the reserves. If this Rs 800 crores will come into circulation, then certainly there will be a rise in prices. There is no doubt about it. The prices are bound to rise as indicated in the Budget itself.

You will kindly see, Sir, that the receipts by bank notes press are estimated to be Rs. 14.22 crores this year as against Rs. 10.91 crores in 1976-77. And this bank note press earning is only on production of currency notes. If in 1976, on account of production of currency notes, the earning from bank note press were only Rs. 10.91 crores, this year provision has been made in the Budget that the earning on this account will be Rs. 14.22 crores—Rs. 4 crores more than what was provided in the last year's Budget. This obviously means that there will be an increase in the production of bank notes. In other words, there will be more currency in circulation in the market. And if there will be more currency in circulation, added to this Rs. 800 crores, 1 would submit that it will definitely have a rising trend of prices. The deficit of only Rs. 72 crores has been shown just for our satisfaction and morale. That is why many people in this country are describing this Budget as 'account fudging', just to manipulate the accounts one way or the other, to show that the deficit is low, even though it is actually Rs. 872 crores.

The Finance Minister has laid the Economic Survey on the Table of the House. The people who prepared this Economic Survey have drawn a very bright picture of the economy of this country. They have drawn a picture of very healthy economy by saying that we have good reserves of foodgrains, industrial output has risen by 10 per cent, big foreign exchange reserve, public saving, capital saving, strength of the money and all that. The same people prepared the Economic Survey in 1976-77. At that time, the same people gave a very dismal picture showing the economic ills of the country. At one point of time, everything was dismal. With the change in the Government, the economic situation is completely different. What else do you call it if it is not intellectual exercise ? It is just like a lawyer appearing from either side. If you appear on behalf of the plaintiff, you argue the case on his side. If you are engaged by the defendant, then you take the brief and argue the case on his side. Are we arguing on behalf of the parties in a court of law or are we trying to see that the basic problems of the society are solved, poverty is removed, ignorance is removed and illiteracy is removed? I would submit that this sort of intellectual exercise is not going to solve any of the problems. There is another point. In paragraph 2, page 1, of his speech, the Finance Minister has been candid enough to say: "It is our firm belief that the open society we cherish

will remain..... " and so on and so forth. Therefore, what the Finance Minister cherishes is an open society. The concept of open society came during the period of John Stuart Mill. Open society is another word for a society of *laissez faire.* It is a free-for-all society. Anybody can exploit any other person. Anybody can earn any amount at the cost of the society. So, Mr. Patel has indirectly indicated that his political philosophy is to establish an open society, a society of *laissez faire* where there will be absolutely no interference by the State in social and economic spheres. I would submit that budget is not just accounting or putting some figures on the credit and debit sides, or

figures on the credit and debit sides, or somehow balancing the expenditure against the revenues. It is an instrument of socio-economic transformation. If you look at the allocation made by the hon. Finance Minister under different heads, you will find that this budget is practically intended to help the private sector. For instance, the Finance Minister has tried to raise 130 crores of rupees by way of new taxtation. 4 P.M. He prepared to give Rs. 220 crores to the private sector by way of incentives by widening the base of the incentives by widening the base of the industrial sector. Then, Sir, the concession which he has given to the corporate sector would clearly show what his political philosophy is. Sir, I would submit that this Budget completely neglects the public sector. Mr. Patel has started taking a step motherly attitude towards his public sector which has reached a commendable height and I would submit that if the public sector is ignored like this, in future or in course of time the whole economy of the country will collapse.

Sir, one more point I would like to say is about this policy of encouraging the private industries to take over sick mills and to carry forward the accumulated losses of these sick mills against the profits earned by the new units. In that case, every private industry will get one sick mill attached to it and earn as much profit as it likes and carry forward the accumulated losses of the sick mill against the profits earned by that new industry. Therefore, whatever profit is earned by the private sector, the State will be deprived of its legitimate share on that private industry while giving away so much towards carry-forward of accumulated losses.

Then, Sir, I would submit that they are borrowing Rs. 800 crores from the special reserve. We do not grudge it. You would have borrowed even a greater amount to bring your deficit to an even lower level. But the point is, how are you going to spend these Rs. 800 crores? And Mr. Sankar Ghose asked : Do you really want to spend this money just to import watches? Is watch a necessity for the people of this country, a country where 60 per cent of people live below the subsistence line? Or, do you want to import capital goods which will help in the production ? And your Budget does not indicate as to how you are going to spend these Rs. 800 crores which you are borrowing from the foreign exchange reserve and whether you are going to import capital goods for the purpose of production or otherwise. You have not indicated that in the Budget. I would submit that the Speech of the hon. Finance Minister reads like an essay by a good college student. Somebody in the Finance Ministry must have prepared this, some intelligent person must have done a very good intellectual exercise, and so many desires have been expressed in the Speech. Why does the Finance Minister feel helpless? If something is to be done, who is to do it? We are not to do it now. If we were doing it in the past, it is not for us now to do it. You are the Finance Minister. You should do what you want to be done. And you express that such and such thing needs to be done in the field of agriculture, such and such thing needs to be done to solve the problem of unemployment, etc. Why don't you do it? Who prevents you from doing it?

You cannot solve it by mere rhetoric. Then, you will kindly see, Sir, that the good intentions that have been expressed in the first nine pages of the speech of the Finance Minister are not reflected in the later portion of Part A of the speech nor at all in Part B of the speech because there is no allocation on those counts. Since Mr. Sankar Ghose has dealt with this question of allocation at some length, I do not want to repeat all those points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Please try to wind up.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA : But, Sir, I would like to submit one more point. So far as the social justice sector is concerned, I would like to know what the provision is that you have made in the Budget. Then, what do you propose in the sector of social justice especially in the matter of land reforms ? Under agriculture you could have indicated what

[Shri Narasingha Prasad Nanda] you intended to do. The other day on the floor of this House while answering a question on behalf of the Agriculture Minister, Mr. Biju Patnaik said that they are going ahead with the land reforms. Well, you are going ahead with the land reforms but have you made any allocation in the Budget? You have shed crocodile tears in the Budget for the Harijans, for the Girijans, the backward classes, weaker sections, marginal farmers and small farmers. But you have not indicated what you intend to do for them. You have not indicated how you are going to raise the standard of living of these people. You have not said how the persons to whom house-sites have been given are going to build even small huts. You have not said how you are going to accelerate the pace of land reforms.

SHRI KHURSHED ALAM KHAN (Delhi) : Are you sure that those house-sites are still available?

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA : At least at some places in villages the house-sites are still available. My question is how does this social service sector which is a step forward in achieving socialism gain from this budget? Of course, Mr. H. M. Patel also talks of Gandhian socialism. Everybody is now talking of socialism, including Mr. H.M. Patel.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : Is it your monopoly only ?

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA : That is a good thing. We do not grudge it at all. But we wish that Prof. Madhu Dandavate understands socialism and shares the same ethos with Mr. H. M. Patel. My simple point is that instead of shedding crocodile tears for these Harijans, Girijans and weaker sections of the community you should have made specific provisions in the Budget for the improvement of their conditions.

SHRI BIJU PATNAIK : Crocodile tears seem to be common on both sides.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA : You were speaking of crocodile teara to us. Now it is our turn to speak of your crocodile tears, and we pay you back with interest.

SHRI KHURSHED ALAM KHAN : Not only interest but compound interest.

SHRI BIJU PATNAIK : Interest is af-ways welcome.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA : I would conclude by saying one more thing. This Budget has given so much relief to the private sector and to private industries in the Finance Bill that I am inclined to believe that the Finance Minister is all out to help the private sector. In other words, he not only cherishes an open society, as 1 said at the outset, but he really wants to establish it and congratulations to him for persuading people like Mr. George Fernandes, Prof. Madhu Dandavate, Mr. Madhu Limaye and the so-called Mr. Rabi Ray and others....

SHRI BIJU PATNAIK : Why so-called?

SHRI NARASINGH PRASAD NANDA : to support a proposal which is completely colourless and not at all inspiring. Thank you, Sir.

SHRI BIJU PATNAIK : Sir, is there a chance of this side also or not ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): Do you want to speak?

SHRI BIJU PATNAIK: Why not? It seems to be a free-for-all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): All right.

SHRI BIJU PATNAIK: 1 had the pleasure and privilege of doing it just a couple of hours back in the Lok Sabha. I had to intervene on behalf of the Finance Minis-!er. I had to do so because the Finance Minister happens to be a very gentle person.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : मान्यवर, मंत्री महोदय को कम से कम इस सदन में जो बातें हुई हैं, उनको सुनना चाहिये और तब उनको इन्टरवीन करना चाहिये उन्होंने बातें सुनी नहीं और भाषण करने..

श्री बीजू पटनायक : यहां भी सुनी हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : यहां पर कितनी बातें आपनेसुनीं ?

श्री बीजू पटनायक : दो भाषण अभी सुने हैं। इसके अतिरिक्त सारे भाषणों के नोट सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं।

SHRI BIJU PATNAIK: This Government is quite efficient We can cany the notes as they are typed out. We have been going on the whole day. We have the notes of what Shri Sankar Ghose said or what this gentleman said and what that gentleman said. You said the same. thing. There is nothing new.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): I did not say anything.

SHRI BIJU PATNAIK : "As a Swatantra man, it is the Swatantra Budget" and all the rest of it—it was the misfortune of Mr. Subramaniam in the Lok Sabha to say that. So, as I mentioned, because the Finance Minister happens to be a very gentle person, he is not used to political vandalism. So, I had to give him my moral support on that score only.

Sir, I told them, they had a very very brilliant Finance Minister in Mr. Subramaniam who was very soon cut short, as I said there, to half a Finance Minister. He was a Finance Minister without knowledge of any revenue that was coming to the State because the Departments of Revenue and Banking and taxes and they said were part of the financial structure of the country, were taken away from the Finance Minister. So he was left with one wing and he could not fly very much.

Sir, 1 would say only two or three points. I will not take too long a time of the House. For instance, take the case of FCI, Food Corporation of India. Rupees two thousand and one hundred crores of bank finance have been employed for that institution and they are paying more than Rs. 200 crores as interest thereon. The Government, Indira Gandhi Government, which occasionally supported socialism and so on, loaded Rs. 200 crores as interest charge on the consumer, poor consumer naturally and this amount of Rs. 2100 crores was taken away from the bank finances which crippled the trade and industry of this country. Yet, Mr. Subramaniam was a good manager of national finance and as I told him that he was the Finance Minister, he was the Planning Minister, he has been the Minister for Science and Technology and he has been the Minister for Steel and also he has been the Minister for Agriculture and therefore, he knows the entire gamut of the Government of India. [asked him that how he could take away Rs. 2100 crores which, otherwise, would have been employed in trade and commerce and industry which crippled the growth, created surplus and large scale unemployment. If he had to manage the finances, why could he not plan the finances from the Consolidated Fund of India ? He had no answer. Secondly, I asked him, since he has been the. Planing Minister and the Finance Minister, why 35 per cent of the nation's districts still remained underdeveloped compared to other districts of India. What sort of planning is this ? Why was not there even distribution of benefits ? There was no answer. For example, in a hill district like Almora, under the C. D programme for which he was also responsible as the concerned Minister earlier, in an area where there was no drinking water, they put a man from the Department of Fisheries. What kind of planning is this ? They put an Industries Department man in an area where there was no electricity. I pointed this out and he agreed. This is micro planning where you sit here, in Delhi, with a few bureaucrates without taking the area into consideration. It should have been micro planning where you go down to the district level and even up to the block level. Even in a block, there are different areas which require different treatments. Without any support of and rapport with the people in the villages and panchayats, these 30 years of planning has resulted in 400 million people living below poverty line. This has been the planning of the Congress in 'he last 30 years. 1 asked him whether he is proud of it. Well, he did not appear to be proud of it. Here, my friend

[Shri Biju Patnaik] from Bolangir says that these sick mills being merged with mills not so sick means evasion of taxes. Fine. What did the previous Government do ? They acquired the sick mills. With whose money ? Yours and mine and, if I may say so, the taxpayer's money. What would you like to have ? The whole purpose of taking over the sick mills one after another is to keep the employment potential going. Now, if a textile mill which is sick, is taken over by the State and they pay so much money to the shareholders, the purpose is to continue in employment nearly 5.000 workmen. Today, if you want to invest in any industry, even in a labour-intensive industry like the textile industry employing 5,000 people, you have to invest not less than Rs. 15 crores. Which is cheaper to the nation ? Is it not wiser to give some relief to a profit-making concern for taking over a sick mill without any charge to the State ? May be it may mean a little loss of revenue. In fact, this policy of taking over the sick mills by profitable companies was an idea mooted by the previous Government. We have only given it practical shape. This becomes a cause for contention because the gentleman has been shouldered out by the people of India.

Take, for example, the small scale industries. This was also a part of the previous Government's plan. Sir, in regard to the small scale sector, you will be surprised to know that 25 per cent of the small scale industries of India is in Maharashtra alone. Do you call that planning ? Four States of this country have more than 59 per cent of the small scale industries. Do you call that planning ? What sort of planning is this ? How can you be proud of it? .

This is the kind of legacy that was left behind to this new Government. 1 told Mr. Subramaniam the other day that this is the kind of legacy they had left behind. Not a buoyant economy as he was trying to project yesterday. It is a sick economy which had been left behind where 400 million people starve. This is what you have left behind. We do not say that it will all be changed overnight. It is on the basis of the earlier Plan and finances already allocated that our Finance Minister had given a certain direction on which he had not much elbowroom. Surely, in the next Budget, he will give more pronounced directions. He was proud of saying that in the last 30 years we developed science and technology.

He happened to be the Minister of Science and Technology. I said: There is no questioning that science and technology are meaningful, required for development of agriculture or industry or modern eco nomic standards, but it should have suited the nation's requirement. And the nation's 70 per cent requirement happens to be agriculture. Did the Science and Technological Department of our country think of developing a number of small tools or tractors or whatever is required for the villager, for the cultivator, for the artisan, for the potter, for the carpenter, fur self-employment or in terms of cottage industries or weavers or whatever it is, where maximum employment can take place with the minimum investment ? Sir, a steel mill needing an investment of Rs. 1000 crores, would employ about 30,000 people. With the same investment of Rs. 1000 crores, in the rural sector it will employ something of the order of six times, i.e. more than 2 lakhs of people. So, where have we worked out the priorities ? Today, I asked Mr. Subramaniam : We have technical schools, polytechnics and so on. The purpose was to create the technical personnel to man industries, dams, power plants and so on. You created the instrument of training. We have today on our roster more than 200,000 of these unemployed people. You have these 200,000 trained people. You have idle mountains containing ore worth thousands and thousands of rupees. You have unlimited water power which is not tapped. So, on the one side you created manpower and on the other you did not provide for the infrastructure. You did not combine man and the nature's resources to create the nation's wealth. What sort of planning is 'hat ? Therefore, when Chaudhuri Charan Singh says that in these 30 years the planning has only created greater unemployment and rural misery, is it not a

fact ? Of course, it is nobody's claim that we shall change it overnight. Even Mr. Subramaniam agreed that it will require about 25 years to do it and for that I have to pat him on the back. This time the Finance Minister has with difficulty brought about an outlay of Rs. 10.000 crores. Sir, you divide Rs. 10,000 crores by 62 crores. It is a grand figure of Rs. 160.

SHRI KALP NATH RAI (Uttar Pradesh) : On a point of information.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): Let him continue.

SHRI KALP NATH RAI: I want to ask one thing. How can I listen to all these things '.' Kindly think of a small scale industry without heavy industry. I want to ask this simple question.

SHRI BIJU PATNAIK: I will come to that. I have not finished. There are no heavy industries, as if. ..

SHRI KALP NATH RAI: You have quoted Chaudhuri Charan Singh. I was listening to you silently, but how cat; 1 keep quiet when you talk about such a man who knows nothing ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN-BIR SINGH): Order, order.

SHRI KALP NATH RAI : Kindly think of small-scale industries. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): Order, order, please Kalp Nath Raiji.

SHRI BIJU PATNAIK: One person saying that another person knows nothing, does not show the intellect of that person. However, I am not contending his intellect. I was saying that it is a grand sum of Rs. 160 per head of investment. I have pleaded with Shri Subramaniam in the other House if it is not the business of the entire House, as I say it is the business of the entire House here, to ensure that Rs. 10,000 crores become Rs. 20,000 crores, or Rs. 40,000 crores, or ten times the amount because that is the quantum of investment that you require to manage the fortunes, even in a small way, of those 400 million people who are below the poverty line. So this has become...

SHRI BIPINPAL DAS (Assam): May 1 ask a simple question ? Is the hon. Minister discussing Mr. Subramaniam or the present Budget ?

SHRI BIJU PATNAIK : I am discussing Mr. Subramaniam for the simple reason that he happened to be the Finance Minister.

SHRI BIPINPAL DAS: He is not a Member of this House.

SHRI BIJU PATNAIK: That is not material whether he is a Member or not. He was the Finance Minister of your party's government.

SHRI BIPINPAL DAS: But we are not discussing the budge: of Mr. Subramaniam. We are discussing the budget of Mr. Patel.

SHRI BIJU PATNAIK : Yes, we are. But I am making a comparative study.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN-BIR SINGH): Hon. Minister should not mention Mr. Subramaniam.

SHRI BIJU PATNAIK : I will not mention Mr. Subramaniam; I will mention the Congress Government. Will that suit you better ?

AN HON'BLE MEMBER : Is it the Economic Survey you are discussing or you are discussing the Budget ?

SHRI BIJU PATNAIK: I am coming to this Budget. Now these are the weaknesses, the great weaknesses in development and five Plans have been framed by the Government of India...

SHRI KALP NATH RAT: You have spoken much. Can you reply to my question ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Order, order. The Minister is not yielding.

SHRI BIJU PATNAIK: I will reply to your questions after I finish.

SHRI KALP NATH RAI: I cannot sit in this House if you do not reply to my questions. Can we have a. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Order, order. The Minister is not yielding.

SHRI BIJU PATNAIK: 1 ;.m coming to that. Why are you so anxious ? I am not disputing your point. If I dispute it, I would have said 'No'. But 1 shall come to it in my own way.

In this manner of planning that has been going on in this country, as I said, 400 million people are left starving. Five Plans have gone by. Now if the Finance Minister of the Janata Party Government says that a clear direction has to be given to the rural economy, is it committing a crime? My hon. friend has said that there is no scope for the small scale industries without the heavy industries. Fine. There is no disagreement on that. But what a small or cottage industry produces shall have to be protected by law against the heavy industry or the well-organised industry ; otherwise it cannot grow, because it needs the minimal investment for maximum employment. It has that potential. So what is this planning? The small scule industries, the cottage industries, the handloom industry and every thing have been allowed to wither away at the altar of the more organised industry which has been your supporter, your financer and mentor.

SHRI KALP NATH RAI : You have been a part of the Congress Government.

SHRI BIJU PATNAIK : The Janata Party did not need them. The janata did not need their money. The Janata Party did not need their money. But they did. They still do. Sir, they have said here that Mr. Patel's Budget is a Swatantra budget. May I say, Sir, a 50-crore-BirIa of 1947 has become a 1000-crore-Birla today. Is it Mr. H. M. Patel's budget... .*(Interruptions)* Is it the Swatantra Party's doing ? In the last two years, they came to control an extra 400 crores. Whose doing is it ? Yours or ours ?

SHRI KALP NATH RAI *: It* is your philosophy.

SHRI BIJU PATNAIK: You have adopted our philosophy! That is why my colleague, Mr. George Fernandes, in the FICCI meeting the other day, described them as rats. In fact, your leader, Shrimati Indira Gandhi, long ago when we were still on talking terms, described them as Worms'. She said : "They are worms. I will treat them as worms, Biju you will see". Not only did she treat them so but she also used them fully to finance them. I will give an instance of the functioning of the Congress Government over the last few years, especially during the last two or three years. She has turned the public sector corporations—of which she is enamoured—like the STC, MMTC and so many other TCs into--as I used the words in the Lok Sabha—a den of thieves and thugs. They used these instruments to amass wealth for individuals . . . *(Interruptions)* I will give you a small instance. Chrome ore worth about Rs. 25 crores was being exported every year. This year I, my colleague Mohan Dharia and the Finance Minister decided to mop up some of the profits on it. On a small amount of Rs. 25 crores, we could mop up Rs. 3-1/2 crores by levying export duty. Now, where was this money going earlier? To the pockets of the individuals of the Congress hierarchy. This is how they have made a mess of this country. That was how the total moral fabric of the administration was broken. Everything was personalised. I am giving you instances (*Interruptions)* ... If you will bear with me for two minutes, 1 shall finish and answer any question you like.

Now coming to the small-scale industries, every panchayat should have a small-scale industry. The simple arithmetic is this : A block in this country today has 60 thou-sant people which means six per cent of the country's population. Seventy per cent of the population are now employed *on* land, with land as the factory. What is sought to be done by the Janta Government is that in the next ten years, 50 per cent of them will be on land, using tools which will be made by the other 50 per cent. This is what is sought to be

done. Therefore, at the panchayat level, at the block level, there should be even planning for industrial growth and the State sector will have to assume greater and greater responsibilities. This is not the Swatantra philosophy. This is the philosophy of even distribution of wealth for 'he removal of economic disparities. It is a question of the development of an 'egalitarian society.

SHRI KALP NATH RAI : On a point of information.

SHRI BIJU PATNAIK : How much in-forma: ion do you want? My friend, I am just coming to your heavy industry. lust wait.

SHRI KALP NATH RAI : What did you do as a Congress Chief Minister?

SHRI BIJU PATNAIK : What I said as a Congress Chief Minister is now going to be implemented by the Janata Government . .(Interruption). I formed the State Corporations. I formed the Forest Corporation, the Construction Corporation, the Small Industries Corporation, the fisheries Corporation and the Industrial Development Corporation. And you gentlemen were against me because I wanted to socialise the dimensions of production. In the year 1964, at the Bhubanesh-war Congress session I introduced the Resolution on Democratic Socialism. So, don't try to teach me. Don't provoke me about it.

Sir, he asked about heavy industry. You ask Mr. Subramaniam who was the Finance Minister of the previous Government . . . *{Interruptions)*

SHRI BIPINPAL DAS : May I ask a small question ?

SHRI BIJU PATNAIK : You may ask but let me finish first.

SHRI BIPINPAL DAS : While the hon. Minister goes on attacking Congressmen of corruption and all that, he should realise that he is sitting in a glass-house. Don't provoke us too much. You are sitting in a glass-house.

SHRI BIJU PATNAIK : Biju Patnaik does not sit in a glass-house.

SHRI BIPINPAL DAS : You are silling in a glass-house; the whole world knows it.

(Interruptions)

SHRI BIJU PATNAIK : These gentle-men were all very brave when I was not present. You bring your charges and see how 1 will demolish them all one by one.

(*Interruptions)*

श्री बिपिन पाल दास : दण्डवते जी बोलें तो हम सुनेंगे । आप से नहीं सुनेंगे ।

SHRI KALP NATH RAI : Yes, yes. (*Interruptions)*

SHRI BIJU PATNAIK : At the altar of the people, telling lies docs not last long. That is why a Commission, wi:h no less a person than Justice Khanna of the Supreme Court has demolished all your charges ruthlessly. That is why the Swa-antra Government fell. Ruthlessly the people threw is out. Therefore, don't try to tell me. 1 have been bisected, trisected and quadrisected. To your great discomfort . . .

SHRI BIPINPAL DAS : It will be done again.

SHRI BIJU PATNAIK : Do it. do it. Do not try these things.

SHRI KALP NATH RAI: Yes. what did the Khanna Commission's Report say? ft is for the honourable House . . . *(Interruptions)*

SHRI BIJU PATNAIK : Read it.

SHRI KALP NATH RAI : What has the Khanna Commission written in its Report ? Let that Report be brought on the Table of the House.

SHRI BIJU PATNAIK : You can read the Khanna Commission's Report. Read it.

SHRI 'KALP NATH RAI : Misconduct of the Minister . . *(interruptions)* conduct of the Minister . . *(Interruption^)*

SHRI BIJU PATNAIK : Yes, I invite you to read it. I would advise you to. .. (*Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Order, order.

SHRI BIJU PATNAIK : 1 am grateful to the honourable Member that he raised this issue. They made a lot of it, but they drew a blank.

SHRI KALP NATH RAI : Bring that Report.

SHRI BIJU PATNAIK : You ask the Home Minister. He will give it to you. The Khanna Commission's Report said clearly that there was no corruption charge proved, that there was no concentration of wealth.. . *(Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Lot us have discussion on the Budget.

SHRI BIJU PATNAIK : If they are ignorant about, it, I cannot help them. But I love these digs. I can demolish them by facts and not by fictions. You had had enough of fictions in this House in my absence, but how you have to deal with facts.

SHRI KHURSHED ALAM KHAN : He talked of the moral support. Now he seems to be prepared for the physical support.

SHRI KALP NATH RAI : The Khanna Commission said against you.

SHRI BIJU PATNAIK : Against me! . .. *(Interruptions).*

SHRI KALP NATH RAI : Don't shout. We also know how to shout.

SHRI BIJU PATNAIK : This gentle. Man is absolutely . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : You can make any point when your turn comes.

SHRI KALP NATH RAI : But, when he speaks against our leader, I cannot tolerate. He must know it.

SHRI BIJU PATNAIK : What is he going to do ? When it was told to us that the earlier Government, the Congress Government, had left us a buoyant economy which we could develop—that we shall, of course develop—I had told the ex-Finance Minister that the buoyant economy might have something to do with the boy but nothing with the national economy. I had told him that they were also the votaries of the public sector and they should know that if I had to develop more steel plants in the heavy sector— aluminium or oil or power or fertilisers, the four major heavy sectors in public sector—we needed outside this Plan about Rs. 10,000 crores, let us say, whereas I was not able to get credit from round the world, I had no rupees left in the country to finance the requirement of even 20 per cent. Rs. 2,000 crores. I had asked the ex-Finance Minister : How do we got about when you have left no rupees for future development. We do have foreign exchange, but we have no rupees. Is this management of the economy ? This type of economy has been handed over to us and we have to build on those shambles with the hopes of the future. All available rupees must go to the poorer sections, the four millions of people constituting the starving sector. But I do not have any rupees needed for development for power, aluminium, steel and fertilizers. So this is the dilemma that the nation is in just now. It is not a question of digging at each other, though I assure the House that I thoroughly enjoy it. But it is a question of putting all the heads together to solve this great national problem. Now, how can we from Rs. 10,000 crores go over to Rs. 20,000 crores of investment without inflation.. .without any inflationary pressures and without having the third currency for deficit budget. This is the task, this is the exercise before us. Therefore, Sir, for development of heavy industries, growth of certain ancillary industries, scale and cottage industries is necessary. Today our handloom export has been of the order of Rs. 150 crores. This could be Rs. 1,500 crores provided we provide the necessary wherewithal to the weavers

and to the other people who deal with handloom and powerlooms. We plan textile mills, a number of them. What is needed is yarn mills to feed the handloom or the powerloom people with yarn in the villages, take over their products and centralise the calendering and mercerizing plant. This is how the world has done, Japan. Switzerland and other countries have done. This is called dispersal. In the last 30 years we have not even attempted at that. So, Sir. this is a national problem, this diversification from the centralised industries to the cottage and the small scale industries for larger employment potential. If that is to be done by law, it cannot be. These are the problems now •exercising the mind of the Janata Government, and in this, I told the ex-Finance Minister, that we needed ideas if they had any. We do not want cross fire. That may go on. In all these 30 years that was going on. but that is not going to serve the cause of the nation. This, Sir. was the point on which I had your permission to be here.

The heavy industries are set up in the public sector. We want to develop them much faster. The rupee content is a problem. but we shall find a way out of it. Now watches are being smuggled. We have to create rupees, Rs. 3,000 crores of foreign exchange is lying idle. We want to convert it into rupees for deflation and at the same time use those rupees for infrastructure development so that we can get another Rs. 10,000 crores foreign money for greater development. We want to take help whether it is from Russia. Japan or whichever country it is; we arc negotiating with the whole world. This is the problem. This is the exercise. This is how the circulation of rupees must lake place.

It is not easy today at all, because of the purchasing power of the people being at the lowest level, to import a thousand items to sell them. Even if I have to import gold, the maximum sale will be Rs. 100 crores. It does not meet the demand of the situation. For edible oils 500 crores worth licences were given, but even 50 crores worth of it was not imported. For watches it is 5 crores. These are the problems of mechanism of the rupee. It is to this task that the Janata Government has started applying its mind. Our development could be faster. It is a difficult task. In this task, we need the support of the other side of the House apart from the little party bickering. That must go on, without that there is no sauce. We thoroughly enjoy them. But we like to get suggestions, constructive suggestions, true suggestions on how to overcome this difficulty jointly. We want a democratic process. We do not wish the Congress Party to be abolished, but you are an Indira rump, not the Congress Party.

SHRI BIPINPAL DAS : I take strong exception to this remark.

SHRI KALP NATH RAI : Don't talk like that.

SHRI BIJU PATNAIK : It is a rump of a party. It is not a party.

SHRI BIPINPAL DAS : It is vulgar language.

SHRI BIJU PATNAIK : It is not the Congres Party as we knew.

SHRI BIPINPAL DAS : This is the Congress Party.

SHRI BIJU PATNAIK : If it were the teal Congress Party, you would not be in this position, if I may say so.

SHRI BIPINPAL DAS: You talk of democracy. . .*(Interruptions).*

SHRI BIJU PATNAIK : I have been in the real Congress Party. But this was, as I said, a rump or a part of whatever it is, ruled by a person. That is not the method of the Congress. That was not the method of the Congress Party. The Congress was always a democratic party. And because you ceased to be a democratic party, you are in this state. *(Interruption)* If you have not learnt your lessons I connot help you.

श्री कल्पनाथ राय : क्या बात करते हो ? इंदिरा गांधी की बात करते हो ? बैठ जाओ।

SHRI BIJU PATNAIK : You must have joined the Congress very late. I never saw you there. But those of the old Congressmen are slowly and steadily leaving you and more and more will leave you because you have become an autocratic party. It is against the tenets of the Congress Party. If you insist on doing it, I cannot help it. If you wish to commit suicide, you are your own master.

SHRI KALP NATH RAI : Don't give us suggestions.

SHRI BIJU PATNAIK : I am not giving you suggestions. The people have done it already. Who am I to say that?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : It is better that the Minister discusses the Budget and not the Congress Party. The Congress Party will take care of itself.

SHRI KALP NATH RAI : He should stop all this nonsense. He should not talk unadulterated nonsense.

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab) : Sir, I do not think it is correct to discuss the internal affairs of a political party. For the first time, there is a recognised Opposition in the country. So far there had been only Opposition groups. To call a recognised Opposition party a rump is not fair on the part of the Minister.

SHRI BIJU PATNAIK : If you are taking objection to the word "rump", 1 will say it is only a part of the Congress ; it was not the whole Congress. I thought "rump" was pretty language . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : I hope you have finished.

SHRI BIJU PATNAIK : T will finish in a second. While I solicit suggestions from the recognised Opposition...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): Let us not discuss the opposition party.

SHRI BIJU PATNAIK : As 1 said, we honour the recognised opposition. We have declared that we shall honour the opposition. That is why we made the leaders of the opposition get . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Now we are discussing the Budget, not the Opposition.

SHRI BIJU PATNAIK : It has a meaning in the whole thing. We gave the leaders of the Opposition both in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha the status of a Cabinet Minister. We deliberately did so for the first time in the history of India.

SHRI KALP NATH RAI : We have given; the Congress has given.

SHRI BIJU PATNAIK : No, you have not. You must have joined the Congress very recently.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : The Opposition did not have the required strength many times.

SHRI BIJU PATNAIK : That does not matter. We have given it only for this reason that the two-party system will grow, democracy will grow, and give-and-take will take place. So far as national issues are concerned, there must be exchange of ideas and thoughts so that the whole nation can progress.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN BIN SINGH) : You should not incite the Opposition Members.

SHRI BIJU PATNAIK : I have not provoked them.

SHRIMATI LAKSHMI KUMARI CHUNDAWAT (Rajasthan) : On a point of order. Sir.

SHRI BIJU PATNAIK : She can have a point of order. I have finished.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : श्रीमन्, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मेरा कहना यह है कि अभी सदन में बजट पर बहस हो रही है । लेकिन अगर इस तरह से बजट पर बहस न करके दूसरी बातों पर सदन का

समय नष्ट किया जाएगा तो यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । इससे सदन का कीमती समय नष्ट होता है। सदन में और भी कई माननीय सदस्य बोलने वाले है। ऐसी स्थिति में क्या सदन का समय बढ़ाया जाएगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : समय बढ़ाना ही होगा।

SHRI BIJU PATNAIK : Sir, 1 was keeping very much within limits till my hon. friend tried to become personal. So 1 had to become personal. That is all there is to it. And as the hon. lady Member there said she did not like the word "rump", 1 changed it to "part". The word "rump" may be expunged from the records.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Shri Yogendra Sharma.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA : Sir, I want to make one submission. The hon. Minister of Steel and Mines intervening in the debate placed before the House so many good ideas as to how the national income of this country will be increased from Rs. 10,000 crores to Rs. 20,000 crores and then to Rs. 30.000 crores and then to Rs. 40,000 crores.

On an open canvas he drew a very beautiful picture of what happened. We were interested in knowing what has been done in the present Budget in that direction. If he had indicated at least some points we would have been happy.

SHRI BIJU PATNAIK : I have already said, the Congress Government had prepared a Budget of Rs. 7800 crores we made it Rs. 10,000 crores. This is only a modest beginning.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Shri Yogendra Sharma.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, जब श्री बीजू पटनायक साहब हम लोगों की बहस में हस्तक्षेप करने के लिये उठे, उस वक्त मैंने आपका ध्यान इस समस्या की ओर खींचा था। इस बारे में मेरा जो अंदेशा था वह सही साबित हुआ कि सदन का उन्होंने जो बशकीमती समय लिया, उससे जिस बजट पर हम अभी बहस कर रहे हैं, जो हमारा आलोच्य विषय है, उसमें कुछ रोशनी नहीं पड़ी । इसलिये मैं कहता हूं कि हमारे सदन का समय बरबाद हुआ। अब वह मंत्री है, मंत्रियों को विशेषाधिकार है कि वह किसी भी समय इन्टरवेंशन कर सकते हैं। पर हम समझते हैं कि मंत्री होने के बाद अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग जरा जिम्मेदारी और शालीनता के साथ करना चाहिये ।

श्री बीजू पटनायक : जिम्मेदारी के साथ ही किया है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आपका परफारमेन्स वास्तविक नहीं था।

मान्यवर, हमारे कांग्रेस दल के श्री शंकर घोष ने इस बजट पर बहस आरम्भ करते हुए या यों कहना चाहिये कि उन्होंने वित्त मंत्री श्री पटेल साहब को बधाई देते हुए, इस बजट पर बहस आरम्भ की । मैं जनता पार्टी के एक दूसरे नेता को उनकी साफगोई के लिये बधाई देने के साथ साथ इस बजट पर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं । जनता पार्टी के एक दूसरे अन्य नेता श्री मधु लिमये को, जिन्होंने बड़ी साफगोई के साथ कहा कि यह बजट जो है वह कांग्रेसी बजट ही है केवल इसमें थोड़ा सा मुलम्मा चढ़ा दिया गया है । इस साफगोई के लिये मैं उनको बधाई देता हूं । इसमें सिर्फ एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं और वह यह कि जो मुलम्मा चढ़ाया गया है, काश, वह पूरा जनता पार्टी का मुलम्मा होता। वह जो मुलम्मा चढ़ाया गया है वह स्वतन्त्री मुलम्मा चढाया गया है, इतना ही मैं श्री मधु लिमये की बात में संशोधन करना चाहता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : बिल्कुल ठीक है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : यह बात सही है कि जो बजट हमारे सामने हैं वह कांग्रेसी बजटों की परम्परा की ही एक कड़ी है । जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में देश की अर्थ व्यवस्था को नई दिशा देने की घोषणा की थी लेकिन वास्तविकता यही है कि यह कांग्रेसी बजटों की परम्परा की एक कड़ी है और कुछ मायनों में तो उससे भी बदतर ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : बिल्कुल ठीक है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : अभी जब पटनायक साहब बोल रहे थे; तो हमारे कांग्रेस दल के बहुत से भाई उत्तेजित हो रहे थे, तो इसको मैं सेडो बाक्सिंग समझता हूं। एक तरह से अभी श्री बीजू पटनायक ने कबूल भी किया कि हमारी बात ऐसी है, इस तरह से तो यहां बहस

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

चल रही थी। लेकिन जनता पार्टी के नेता बजट के नाम पर इस तरह की बहस कर रहे हैं। मैं तो चाहता था कि जनता पार्टी के और भी नेता इस पर बोलें और सफाई हो जाय। प्रो० दण्डवते जी को भी बोलना चाहिये इससे और भी सफाई हो जायेगी। लेकिन दो चार दिन पहले हमने आकाशवाणी आल इंडिया रेडियो से इस देश के बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ की वार्ता सुनी। हमने समझा कि भारत के संविधान की बात होगी, क्योंकि वे एक विधि विशेषज्ञ हैं वह हैं श्री पालकीवाला। तो हमने यह आशा की थी कि कांस्टीट्यूशन पर कुछ बहस होगी, कांस्टीट्यूशन पर कोई वार्ता होगी, नहीं साहब यह तो सब बजट पर वार्ता हुई। बजट पर भारत की जनता को रोशनी देने के लिये पालकीवाला साहब आल इंडिया रेडियो पर आते हैं तो हमने सुना...

एक माननीय सदस्य : क्या आप रेडियो भी सुनते हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : कभी कभी सुन लेते हैं।

SHRI BIJU PATNAIK : I think, if I remember alright, on the last Government's Budget Shri Birla also spoke a great deal.

SHRI KALP NATH RAI : Shri Birla is supporting you people now.

SHRI **BIJU** PATNAIK : Not at all.

श्री योगेन्द्र शर्मा : श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था इस बजट पर जिस पर हम अब बहस कर रहे हैं कि उस की वकालत करने के लिये पालकीवाला को आल इंडिया रेडियो पर लाया गया।

एक माननीय सदस्य : क्या बुरा है भाई अगर आल इंडिया रेडियो पर लाया गया।

SHRI BIJU PATNAIK : All India Radio is now free for you and everybody.

श्री योगेन्द्र शर्मा : हम पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहते। हम जानते हैं बिरला साहब और टाटा साहब जिनके बारे में बात कर रहे हैं उन के बारे में हम लोगों को भी विचार करने का मौका मिलेगा; लेकिन आश्चर्य की बात है कि समाजवादी और गांधीवादी फिलास्फी को जनता पार्टी तैयार करती है, उस फिलास्फी को कार्य रूप देने के लिये बजट की वकालत के लिये पालकीवाला साहब को जिन्होंने गांधीजी के स्वदेशी, स्वावलम्बन, समता, सादगी के सिद्धान्तों की आलोचना की थी आज जनता पार्टी के बजट की वकालत करने के लिये खड़ा किया जा रहा है। श्रीमन्, जिस तरह से बजट तैयार किया गया, बजट तैयार करने की प्रक्रिया बजट के चरित्र को दिखाती है हमारे वित्त मंत्री ने उद्योगपतियों, व्यापारपतियों के प्रतिनिधियों से सलाह मशविरा किया है। ठीक है इसमें हम को कोई एतराज नहीं है, और करना भी नहीं चाहिये। वे भी हमारे देश के आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। परन्तु उससे अधिक महत्वपूर्ण भाग हमारे देश का मजदूर वर्ग है जिनकी मेहनत से ही सारी सम्पत्ति पैदा होती है। खेद की बात है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में किसी यूनियन के प्रतिनिधि से सलाह मशविरा नहीं किया है। क्या आपका यह दृष्टिकोण समाजवादी है? क्या यह गांधीवादी दृष्टिकोण है? तो पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से सलाहमशविरा आपने किया है लेकिन मजदूर वर्ग जिसकी मेहनत और जिसकी पैदावार करने की क्षमता पर हमारे भारत का अर्थ तन्त्र निर्भर करता है, उसके प्रतिनिधियों से आपने कोई बात नहीं की है।

देहाती क्षेत्रों के विकास की बहुत चर्चा होती है, यह चर्चा पहली बार नहीं हुई है। देखा जाये तो किसानों के नाम पर पिछले दिनों काफी आंसू बहाये गये, हमारे कांग्रेस के भाई माफ करेंगे, अब जनता पार्टी वाले आंसू बहा रहे हैं।

श्री बीजू पटनायक : हमने तो आंसू नहीं बहाये।

श्री योगेन्द्र शर्मा : तो किसानों के लिये, देहाती क्षेत्रों के लिये घड़ियाली आंसू बहाते जा रहे हैं और इतने बहाये जाते हैं कि हमारे देहाती क्षेत्र में किसान कहते हैं कि केकरा केकरा नाम गिनाबों देस में सबै लुटरवा।

श्री बीजू पटनायक : समझा दीजिये : मैथिली में है किसमें है ?

श्री योगेन्द्र शर्मा : किस किस का नाम गिनाये, सभी लुटेरे हैं, सभी धोकेबाज हैं, सभी हमारी बात करते हैं और काम करते हैं टाटा और बिड़ला का।

हमने इस बजट की देखने के कोशिश की कि क्या किसानों और देहाती क्षेत्र को प्राथमिकता,

वरीयता, विशेष महत्व देने की जो बातें हैं उनकी तरफ कोई ध्यान इस बजट में दिया गया है? हमारे मित्र श्री सिंह ने भी यह शिकायत की और हम समझते हैं इस बिना पर उन्होंने बहुत सही बात कही। कुछ है ही नहीं इसमें। यह उतना ही दिखाता है जितना पहले दिखाते थे। मैं चाहता हूं—पटनायक साहब आपने इन्टरवीन किया—आप हमें दिखलाते कोई ऐसी बात तो हमें खुशी होती। दूसरी तरफ, हमारे मित्र शंकर घोष साहब ने बतला दिया कि एक पैसा आप ज्यादा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बात ज्यादा दे रहे हैं।

तो मेरा कहना यह है कि किसानों और देहातों के प्रति उपेक्षा हुई है, उपेक्षा हो रही है, इस बजट में भी उपेक्षा है, आगे भी उपेक्षा होगी। तब तक उपेक्षा होगी जब तक टाटा-बिड़ला का जादू आपके सिर पर है...

श्री बीजू पटनायक : हमारे सिर पर है। उधर बोलिये।

श्री योगेन्द्र शर्मा : हमने तो कहा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और जो इनके साथ थे अब जनता पार्टी में चले गये।

डा० राम कृपाल सिंह : टाटा-बिड़ला को जो सिर पर उठाने थे उनको ये सिर पर उठाए थे।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैंने शुरू में ही कहा श्रीमन्, कि यह जो बजट है यह कांग्रेसी परम्परा का बजट है, उसी की एक कड़ी है। अब लोग नाराज होते हैं। (*Interruption*) दो पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है..

श्री बीजू पटनायक : इमरजेन्सी में ऐसा भाषण करते तो कितना अच्छा होता?

श्री योगेन्द्र शर्मा : यही इमरजेन्सी में होता था। क्या आपने नहीं सुना है कि इमरजेन्सी के दौरान रोज बयान निकलता था—बैन सी० पी० आई०...

श्री बीजू पटनायक : निकलता था?

श्री योगेन्द्र शर्मा : भूल गये?

श्री बीजू पटनायक : हम जेल में थे।

(*Interruption*)

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : आप जरा बजट पर वार्ता कीजिए।

श्री योगेन्द्र शर्मा : अब हम क्या करें?

श्री बीजू पटनायक : तो मैं चला जाऊं?

श्री योगेन्द्र शर्मा : आप नहीं रहेंगे तो प्रेरणा नहीं मिलेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : मंत्री जी के लिये मुश्किल यह है कि मुख्य मंत्री रह चुके हैं। मुख्य मंत्री दूसरों की सुनते नहीं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि यदि देश की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिये आप उद्योगपतियों से, व्यापारियों से सलाह-मशविरा करते हैं तो क्या भारत के मजदूरों के प्रतिनिधियों से भी सलाह किया है? ट्रेड यूनियनों से भी सलाह मशविरा किया है बजट पेश करने से पहले? वाशिंगटन गये तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा में जाने की इतनी बैचैनी थी। हमारा ख्याल है कि पटनायक साहब मेरी बात सुन रहे हैं। हम अंगरेजी में नहीं बोल सकते हैं, इसमें हमारी लाचारी है...

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : वह सब समझते हैं, एक एक शब्द।

श्री योगेन्द्र शर्मा : यहां के उद्योगपतियों से सलाह मशविरा करने के पश्चात् वे तीर्थस्थान चले गये। और तीर्थस्थान में जाने की इतनी जल्दी थी कि मंत्रियों के लिये एयर इंडिया से सफर करने का जो नियम है उस को भी तोड़ दिया। उन्होंने तीर्थस्थान से आकर यह बजट पेश किया। इस बजट में है क्या?

बहुत गीत गाया गया है कि यह घाटे का बजट नहीं है, बहुत कम घाटा है 72 करोड़ का।

SHRI BIJU PATNAIK : Is he referring to the Finance Minister's visit to the World Bank ?

AN HON. MEMBER : By Concord.

SHRI BIJU PATNAIK : What is wrong with Concord ? He can travel by rocket if he likes...

(*Interruptions*)

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं बयान कर रहा था जो हकीकत है।

श्री बीजू पटनायक : मास्को की तीर्थयात्रा कर के नहीं आये, यह तकलीफ है आप को।

श्री योगेन्द्र शर्मा : इस की हम आशा उन से नहीं करते।

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : आपस में कोई बात न कीजिये।

श्री बीजू पटनायक : उन की जगह में जा रहा हूं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : इस बात का बहुत ढोल पीटा जा रहा है कि सिर्फ 72 करोड़ रुपए के घाटे का बजट है।

श्री बीजू पटनायक : उस को बढ़ा देंगे आप कहें तो।

श्री योगेन्द्र शर्मा : हम कहते हैं कि यह धोखा है। इस सन्तुलित या कम घाटे के बजट के पीछे द्रविड़ प्राणायाम है । द्रविड़ प्राणायाम क्या है समझते हैं?

श्री बीजू पटनायक : बताइये क्या है?

श्री योगेन्द्र शर्मा : नाक ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे घूम कर पकड़ने को द्रविड़ प्राणायाम कहते हैं।

श्री बीजू पटायक : फैक्ट्स बताइये । Facts, not insinuations.

श्री योगेन्द्र शर्मा : फैक्ट्स पर आ रहा हूं। द्रविड़ प्राणायाम यह है कि विदेशी मुद्राकोष की जमानत पर 800 करोड़ रुपये कर्ज लिये और अनिवार्य जमा बचत की किश्त जो जुलाई में मिलने वाली थी उस को आपने नहीं दिया । तो इस माने में यदि आप सीधी-सीधी बात करते तो यह 1350-1400 करोड़ रुपये का घाटे का बजट होता । लेकिन आप ने द्रविड़ प्राणायाम करके बहुत ही कम घाटे का बजट बनाने की कोशिश की है।

श्रीमन्, अब हम यह देखें कि इस बजट में...

डा० राम कृपाल सिंह : इस पोइन्ट को जरा साफ करिये, यह साफ नहीं हुआ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : डा० साहब, हमारी बात कभी आप को साफ नहीं होगी।

अब हम इस बात को देखें कि यह जो बजट है इसमें किस से लिया और किसको दिया। बजट यदि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एक अस्त्र है तो वह अस्त्र किस पर चल रहा है, किस के लिये चल रहा है, इस को देखने के लिये देखना पड़ेगा कि किस से लिया जा रहा है और किस को दिया जा रहा है ।

श्री बीजू पटनायक : जिस से लिया उसी को दिया।

श्री योगेन्द्र शर्मा : काश ऐसा होता। लिया है गरीबों से और दिया है अमीरों को । ठीक उससे उल्टा जो आप ने अपने घोषणापत्र में लिखा था।

श्री बीजू पटनायक : हिसाब तो बताइये। It is 40 per cent

श्री योगेन्द्र शर्मा : हिसाब बता रहा हूं। संपत्ति कर में इन्होंने आधे फीसदी की वृद्धि की है ।

SHRI BIJU PATNAIK : 40 per cent.

श्री योगेन्द्र शर्मा : आप बतलाइयेगा कैसे?

SHRI BIJU PATNAIK : Two-and-a-half per cent to three-and-a-half per cent : Is it not 40 per cent increase ? It is elementary arithmetic. From 2-1/2 to 3-1/2 percent means 40 per cent increase.

श्री योगेन्द्र शर्मा : हम इन की तरह उद्योग-पति नहीं जो दो खाते रखते हों। ढाई से तीन प्रतिशत हो गया।

श्री बीजू पटनायक : उद्योगपति होते तो हिसाब होता।

श्री योगेन्द्र शर्मा : ढाई से तीन परसेंट होना क्या आधा परसेंट नहीं है? हम दूसरी बही नहीं रखते?

SHRI BIJU PATNAIK : This is the Communist method of betraying facts .....
(Interruptions)

श्री योगेन्द्र शर्मा : अब आप यह फैसला करें कि ढाई से तीन परसेंट...

श्री बीजू पटनायक : साढ़े तीन परसेंट।

श्री योगेन्द्र शर्मा : इस से इन को कितना मिलेगा ? दस करोड़ । लेकिन बीड़ी पर कर उन्होंने दूना कर दिया।

श्री बीजू पटनायक : बीड़ी नहीं पीना चाहिए।

श्री योगेन्द्र शर्मा : लेकिन सिगार पीना चाहिए ? आप को बीड़ी पर दूना करने के बाद 45 करोड़ मिला है। तो देखा जाय कि किससे लिया और किसको दिया और इसके साथ ही आप उनके समतावादी दृष्टिकोण को लीजिए। उनकी नीति है कि जो बड़े करोड़पति हैं उनसे आधा परसेंट और ज्यादा लिया जाय, उनसे कुल दस

करोड़ लिया जाय लेकिन जो बीड़ी पीने वाला है गांव का किसान उस से 45 करोड़ लिया जाय ।

श्री बीजू पटनायक : इस तरह से आप बात को पेश करेंगे तो यह मजाक हो जायगा । एक रुपया एक हजार में बढ़ाया है यह क्या बहुत ज्यादा हो गया । और जो शराब पीने वाला है उसका तो दो सौ परसेंट बढ़ा दिया है ।

श्री योगेंद्र शर्मा : संपत्ति कर से आप को दस करोड़ अधिक मिलेंगे और बीड़ी कर से आप को 45 करोड़ मिलेंगे । यह आप का समतावादी बजट है । यह गरीबों को मारने वाला अमीरों का बजट है ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : जिनके घर में फारेन विकर मिलती है उनके भी केस बिदड़ा हो जाते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : आर्डर । आर्डर ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं इस सिलसिले में एक बात और निवेदन करूंगा कि संपत्ति कर जो है वह थोड़ा है । मैं यह अर्ज करूंगा कि आपात काल के पहले जो संपत्ति कर था और जिसमें आपात काल के दौरान छूट दी गयी थी आप के मित्रों के जरिये वह पुराने वाले थे या नये वाले, यह मैं नहीं कह सकता . . .

श्री बीजू पटनायक : आप के मित्र होंगे, हमारे नहीं हैं ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : अभी आप लोग आपस में लड़ रहे थे . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : आप लोग आपस में बात न करिये ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी । इतने भारी भरकम मंत्री जी, उड़ीसा के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, अगर यही टोका टोकी करेंगे तो कैसे चलेगा ।

श्री बीजू पटनायक : आप के कहने से हमने डिफेंस बजट घटा दिया है ।

(Interruption)

श्री योगेन्द्र शर्मा : डिफेंस तो बाहर के लिये है, भीतरी भाग के लिये नहीं होता । आपकी पुरानी आदत छूटेगी नहीं । तो मैं कह रहा था कि यह जो संपत्ति कर बढ़ाया गया है वह जब सुब्रह्मण्यम साहब वित्त मंत्री थे उस समय घटाया गया था । उसके पहले चव्हाण साहब वित्त मंत्री थे । उस वक्त जो संपत्ति कर था अभी जो आपने बढ़ाया है उसके बावजूद वह कम है और इस काम में कांग्रेस के लोग कह सकते हैं कि चव्हाण साहब के वित्त मंत्रित्व काल में उन्होंने लखपतियों और करोड़पतियों पर ज्यादा हाथ डाला था । आप यह नहीं कह सकते । आप ने तो उन पर केवल आधा परसेंट ज्यादा बढ़ाया है ।

श्री बीजू पटनायक : फिर आप आधा परसेंट की बात कह रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : यह जो हमारा हिसाब है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : इसको तो वित्त मंत्री जी ठीक कर देंगे, पटनायक साहब, आप क्यों इस हिसाब किताब में पड़ते हैं । आप अपना लोहा व इस्पात का हिसाब करिये इसको वित्त मंत्री पर छोड़िये ।

SHRI BIJU PATNAIK : Sir, 40 per cent increase is reduced to half per cent, it looks odd.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं तो रेट की बात कर रहा था । इसी तरह से आय कर की जो सबसे ऊंची दर है उस को आप ले लें । उसमें तीन फीसदी बढ़ती गयी है ।

श्री बीजू पटनायक : यह मानता हूं ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : और आपात काल में इसमें 21 फीसदी की कटौती कर दी गयी थी । आपात काल के पहले जबकि चव्हाण साहब वित्त मंत्री थे उस वक्त जो आयकर की सबसे ऊंची दर थी । अभी जो आपने तीन परसेंट बढ़ायी है उस बढ़ोत्तरी के बावजूद चव्हाण साहब के वित्त मंत्रित्व काल में जो दर थी उससे यह कम है ।

श्री बीजू पटनायक : जो पहले था उससे बढ़ाया ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आपात्काल में उनको जो छूट दे दी गई है उनमें उन्होंने 19-20 करने की कोशिश की है लेकिन उसके पहले जो सबसे ऊंची आय कर की दर थी या संपत्ति कर की दर थी, अभी भी आपने जो दर प्रस्तावित की है वह उससे कम है । इसके माने कांग्रेस वाले यह कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े-बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों और समृद्धिशाली लोगों के ऊपर ज्यादा हाथ मारा था ताकि हम कमजोर लोगों को ज्यादा दे

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

सकें। आपने जो अपने घोषणापत्र में कहा है कि सबसे पिछड़े हुए लोगों का जीवन स्तर उठाने के काम को ही पार्टी प्राथमिकता देगी, यह दूसरी तरह की बात है। पार्टी उच्चस्थ वर्गों को नीचे उतारकर, आप जैसे लोगों को नीचे उतारकर निचले वर्गों को ऊंचा उठायेगी, यह आपने घोषणा की।

श्री बीजू पटनायक : वह हमने नहीं लिखा है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : यह धोखा है, यह धोखा किया है आपने।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): No conversation please.

SHRI BIJU PATNAIK : This is a place for conversation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : No conversation please.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI (Uttar Pradesh) : May I request Mr. Biju Patnaik to maintain the dignity of the House ? You arc simply going on talking like that. You are a Minister. Please maintain the dignity of the House.

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : आज राज्यसभा का समारोह है और हमें साढ़े पांच बजे उठना होगा। मेरा ख्याल है कि सदन इस बात से सहमत है कि साढ़े पांच बजे सदन की कार्यवाही स्थगित हो। शर्मा जी आप कितना और समय लेंगे ?

श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या करें साहब, बीजू पटनायक साहब ने हमारा समय ले लिया। तो मैं यह कह रहा था कि अभी वकालत की गई इस बात की कि बाहर से घड़ियां मंगाई जायें। हमको इस बात पर ऐतराज नहीं है। बाहर से घड़ियां मंगाने पर जो सीमा-शुल्क था वह घटा दिया गया और हमारे देश की जो बनी हुई घड़ियां हैं और देश में घड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में बहुत से छोटे-छोटे कारखाने, छोटे-छोटे उद्योग पैदा हो गये हैं, काटेज इंडस्ट्रीज पैदा हो गई हैं तो यहां की बनी हुई घड़ियों पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया। यह कौन सी फिलासाफी है, कौन सी दिशा है। क्या यह स्वदेशी को बढ़ावा देना है? क्या यह गांधी जी की आइडियालाजी है? क्या गांधी जी ने पूरे देश को इसलिए तैयार किया था कि आप यहां स्वदेशी घड़ी उद्योग को बरबाद करके विदेशी उद्योग को बढ़ावा दें? फिर कहते हैं कि यह समतावादी बजट है।

एक दूसरा प्रश्न और ले लें। सभी रोजगार बढ़ाने की बात करते हैं। इन्होंने भी रोजगार बढ़ाने की बात कही है और ज्यों-ज्यों हम रोजगार बढ़ाने की बात करते हैं, त्यों-त्यों बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बदकिस्मती से। अब रोजगार बढ़ाने के नाम पर इन्होंने क्या किया ? पूंजी-निवेश भत्ता देने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, पिछले साल, और पिछले साल में 45 करोड़ रुपये दिये गये थे लेकिन वह अब बढ़कर 225 करोड़ हो गये। तो पूंजी-निवेश भत्ता बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। न केवल नेशनल बल्कि मल्टी-नेशनल भी यदि यहां पूंजी लगायेंगे तो इनकी पूंजी लगाने में भत्ता मिलेगा। यह 45 करोड़ से शुरू हुआ लेकिन इस बार इन्होंने 225 करोड़ कर दिया जबकि यह कहते हैं हम समतावादी हैं, यह कहते हैं हम बेरोजगारी की समस्या हल करेंगे। यदि विदेशी पूंजी और देशी पूंजी अधिकाधिक हमारे देश में फैले तो उनको फैलाने की सिर्फ एक ही मंशा होती है, एक ही नीयत होती है कि अधिक से अधिक मुनाफा और अधिक से अधिक मुनाफा लेने के लिये वह कम से कम काम लें और अधिक से अधिक श्रम शोषण करें। ऐसी स्थिति में समतावादी समाज की स्थापना नहीं होगी। जिस दिशा की ओर आप चल रहे हैं वह दिशा दूसरी है। पूंजी निवेश के जरिये से आप भारत में विदेशी और देशी इजारेदारी की स्थिति को और मजबूत करने जा रहे हैं।

SHRI BIJU PATNAIK : Do you mean in the public sector ?

श्री योगेन्द्र शर्मा : पब्लिक सैक्टर भी एक विचारणीय विषय है। पब्लिक सैक्टर हमारे देश की जनता की गाढ़ी कमाई की उपज है, जिस पर हम को नाज है, नाज इस मायने में है कि यदि पाब्लिक सैक्टर नहीं होता तो हम आर्थिक स्वावलम्बन की बात, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकते थे। बीजू पटनायक साहब को मालूम नहीं होगा कि 1931 में कराची कांग्रेस में जो मौलिक प्रस्ताव पास हुआ था उस प्रस्ताव में कहा गया था कि देश के जितने बुनियादी उद्योग धंधे होंगे वे सब राज्य के हाथ में होंगे, वे बुनियादी उद्योग धंधे राज्यों के हाथ में होंगे। शायद उस वक्त आप कांग्रेस में नहीं होंगे।

श्री कल्पनाथ राय : उस वक्त कांग्रेस में ही थे ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आज उसी परम्परा का तकाजा है कि देश में तमाम बुनियादी उद्योग धंधे राज्य के क्षेत्र में हैं ।

SHRI BIJU PATNAIK : One point, Sir. Will it be so even if this investment is made in the public sector ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : The Member is not yielding.

SHRI BIJU PATNAIK : Sir, I would like to learn by his knowledge. Supposing Rs. 10,000 crores are invested in the public sector, would it be objectionable ?

THE- VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Order, order, please.

SHRI BIJU PATNAIK : What does it mean ?

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, मंत्री महोदय को यह कहूंगा कि यदि मेरी बात को पूरी सुन लें और कोई सवाल रह जाए तो वह बाद में पूछ लें मैं जवाब दे दूंगा क्योंकि बीच में बोलने से तारतम्य टूट जाता है ।

जो पूंजी निवेश में भत्ता दिये जाने की बात है इस भत्ता देने में कोई भेद-भाव नहीं किया गया है। यह नहीं देखा गया है कि यह विदेशी है या देशी, छोटा पूंजीपति है या बड़ा पूंजीपति । छोटे को बड़े के हवाले भी न किया जाए क्योंकि छोटी मछली को अगर बड़ी मछली के हवाले कर देंगे तो बड़ी मछली और मोटी होती जाएगी। इस बजट को देखने से लगता है कि छोटे और भी छोटे हो जायेंगे आपकी फिलोसफी यही है । यदि आप हारवैस्टर बनाने का कारखाना शुरू करेंगे, कंप्यूटर बनाने का कारखाना शुरू करेंगे...

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : साढ़े पांच बजे तक समाप्त करना है ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : हम तो आपकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे ।

श्री खुरशीद आलम खान : कोई काम की बात हो तो ठीक है ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : काम की बात तो यहां है ही नहीं, बात की बात है। काम की बात तो वे ही करते हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि हारवैस्टर बनाने का कारखाना हो या कंप्यूटर बनाने का कारखाना हो क्या उस पर भी निवेश में भत्ता मिलेगा ? मेरा कहना यह है कि इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे पता लगता है कि रोजगार जो इस वक्त हैं उनमें कमी आ जाएगी जब कि यह कहते हैं कि रोजगार बढ़ाने के लिये हम काम कर रहे हैं।

अभी-अभी कहा गया कि बीमार मिलों को जो तंदरुस्त मिलें हैं उनको दे दें तो माल सस्ता हो जाएगा । मेरा कहना यह है कि यह एक अजीब दलील है । इससे माल सस्ता नहीं होगा । देखने में यह बात सही हो सकती है लेकिन इसका नतीजा यही होगा कि देश में जो अभी पूंजीपति हैं वे और भी मोटे हो जायेंगे । धनी जो हैं वे और धनी हो जायेंगे । आपने अपने घोषणापत्र में कहा है कि धनी को हम नीचे लायेंगे और गरीब को ऊंचा उठायेंगे लेकिन इसका नतीजा यह होगा कि धनी और भी धनी होगा और गरीब और भी गरीब होगा ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : श्रीमन्, आजकल कृषि के विकास के जरिए से रोजगार बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत जैसे देश में जहां 70 फीसदी लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं, कृषि के विकास के बिना राष्ट्रीय विकास नहीं हो सकता है। लेकिन कृषि का विकास किस तरह से हो, यह एक विचारणीय प्रश्न है । इस सिलसिले में खुद वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में जापान की मिसाल दी है । जापान में प्रति एकड़ उत्पादन का स्तर भारत से बहुत अधिक है । काश, हम भी वैसा कर पाते ? जापान कैसे इसको कर सका, इस पर विचार करने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त स्वीट्जरलैण्ड की बात कही जाती है । मैं समझता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जापान और अन्य यूरोप के देश अपने उत्पादन में इस प्रकार की वृद्धि कैसे कर सके, इसकी छानबीन करने की

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

जरूरत है। मैं समझता हूं कि इसका प्रधान कारण यह है कि वहां पर भूमि सुधार का काम सबसे पहले हाथ में लिया गया। जापान के अन्दर 10 एकड़ से अधिक जमीन रखने की आवश्यकता नहीं है और न ही इसकी इजाजत है।

श्री भानु प्रताप सिंह : आप यह बहुत पहले की बात कह रहे हैं। आज वहां पर यह स्थिति नहीं है। उन्होंने अब भूमि की सीलिंग बढ़ा दी है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं मैकार्थर के जमाने की बात कह रहा हूं। उस वक्त वहां पर लैण्ड रिफार्म करके प्रति व्यक्ति 10 एकड़ की सीमा निश्चित की गई थी।

श्री नागेश्वरी प्रसाद शाही : (उत्तर प्रदेश) इसका मतलब तो यह हुआ कि यहां भी सीलिंग बढ़ाई जाएगी क्योंकि जापान में सीलिंग बढ़ाई गई है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : श्रीमन्, मैं समझता हूं कि खेती का विकास भी टेक्नोलाजी के विकास से सम्बन्धित है। बिना टेक्नोलोजी के विकास के हमारे देश में खेती का विकास नहीं हो सकता है। बिना टेक्नोलोजी के विकास के हरित क्रांति कृषि क्रांति नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में गांवों के अन्दर टेक्नोलोजी के विकास के साथ-साथ लैण्ड रिफार्म भी अत्यन्त आवश्यक है। जब तक गांवों के अन्दर भूमि सुधार नहीं होगा तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो सकता है। अगर भूमि सुधार नहीं होगा तो कृषि से जो आमदनी होगी उनमें विषमता पैदा हो जाएगी। इसलिए भूमि सुधार को सबसे ऊंची प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने जनता के साथ जो वायदे किये थे, मैं समझता हूं कि उन वायदों के खिलाफ यह बजट जाता है। यह वायदा-खिलाफी बजट है। आपने वायदा किया था कि सी० डी० एस० खत्म किया जाएगा, लेकिन आप उसको रखे हुए हैं। आपने कहा था कि मजदूरों को कम से कम 8⅓ फीसदी बोनस दिया जायेगा, लेकिन आज मजदूर मारे-मारे फिर रहे हैं, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आपने वायदा किया था कि सेल्स टैक्स समाप्त किया जाएगा, लेकिन आज आप सेल्स टैक्स को बनाये हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह वायदा-खिलाफी का बजट है।

एक बात अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस दल विरोध में बैठा हुआ है। मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि कांग्रेस की सरकार इस देश में मंहगाई को कम नहीं कर सकी और बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं कर सकी, इसलिए उसको हार का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार को भी समाप्त नहीं कर सकी। लेकिन जनता पार्टी की सरकार के तीन महीनों के अन्दर ही उसको मिलने वाले वोटों में 15—20 प्रतिशत की कमी हो गई है। यह इस बात का संकेत है कि आप लोग भी मंहगाई और भ्रष्टाचार की समस्या को हल नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस तो अपनी परम्परा के कारण बहुत दिनों तक टिकी रही परन्तु जनता आपको पांच साल भी नहीं सहन करेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि...

उप-सभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आप सही मायनों में जनता-मुखी बनें। आपने जो अपने घोषणा-पत्र में कहा है, उसका पालन करें न कि उसका उल्लघंन।

SHRI BIPINPAL DAS : Sir, I would like to make submission. The way this debate is progressing, it appears we shall not be able to complete the debate within four days time. This is a very important matter. I do not want that any Member of this House should be deprived of an opportunity of taking part in this debate. Therefore. I would like the Leader of the House to take note of this fact and, it necessary, there should be an extension of the House by one day to complete this debate. This is a very important matter. We do not want that any Member should be deprived of an opportunity of taking part in this debate.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं आपके मार्फत ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जनरल डिसकशन पर दूसरे सदन में 3 दिन का समय रखा गया है जबकि हमारे यहां इसके लिये 4 दिन रखे गये हैं। शुरू से लेकर हमने इस बात की व्यवस्था कर रखी है। इससे पहले हमेशा परम्परा 3 दिन रही है परन्तु यह पार्लमेंटरी एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था और सरकार ने इसे स्वीकार किया कि यह बहस हम इस सदन में चार दिन करेंगे।

SHRI BIPINPAL DAS : J accept this position. But my only request to the Leader of the House is that he should see that this debate progresses peacefully and in an orderly manner so that all Members who want to speak on the Budget can have an opportunity and we could complete the debate in time.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं नहीं समझता कि कोई समय इसके लिये बढ़ाया जाये ।

SHRI BHUPESH GUPTA : The Lok Sabha discusses the Demands for Grants. We do not do it. Therefore, it is not a generosity shown to us that we have been given four days for general discussion *while* the other House has been given three days, I hope Mr. Advani, being a Member of this House, would be alive to this handicap from which we suffer. Therefore, if the Members feel that the debate should be extended by a day, there should not be any objection to it on his part. After all, we are not going to sit for a whole month to take up the Demands for Grants and discuss them item by item. Therefore, it stands to reason that this request by our friend be accepted by the Government.

Then Sir, the announcement in regard to repeal of MISA should be made before we leave. He should say what he is going to do about it.

SHRI LAL K. ADVANI : He is perhaps simply suggesting that the interruption by the Minister should not be there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Shri Bipinpal Das is positively suggesting for extension.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : उप-सभाध्यक्ष जी, मेरा इस संदर्भ में निवेदन यह है कि अभी जिस प्रकार से माननीय बीजू पटनायक ने इसमें इन्टरवेंशन किया, उससे हमारे दो घंटे गये, नहीं तो हम इस पर 5-6 व्यक्ति बोल सकते थे । हमारा डर यह है कि आगे अब हमें इस बारे में कुछ समय बोलना पड़ेगा । यदि उनका इन्टरवेंशन न होता तो हम अब तक बोल गये होते ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned at thirty-three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 22nd June. 1977.

MGIPRRND—7RSS/77—U-NS—3-8-77—595.